संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री शिव चन्द्र झा : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

CONSTITUTION (AMENDMENT) *BILL

(*Amendment of Article 233*)

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री शिव चन्द्र झा : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

16.07 hrs.

FOREIGN AID (MAINTENANCE OF ACCOUNT) BILL—*Contd.*

By Shri Kanwar Lal Gupta

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall now take up further consideration of the Foreign Aid (Maintenance of the Account) Bill moved by Shri Kanwar Lal Gupta. Two hours were allotted and 1½ hours had been taken. Only thirty minutes remain and we can accommodate one or two Members. Then the Minister will speak and the Mover will reply. We have to complete all this within thirty minutes.

SHRI YASHPAL SINGH (Dehradun) : What about my amendment?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You were not here when the time came.

SHRI YASHPAL SINGH : Kindly permit me to move it now.

MR. DEPUTY SPEAKER : No not now.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस फारेन एड विधेयक की मुखालिफत करता हूं । यह बात जरूर है कि बाहर से पैसा लेकर कुछ व्यक्ति या कुछ संस्थायें देश की राजनैतिक और आर्थिक बनावट में खराबियां ला रहीं हैं, लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि यदि देश की तरक्की और विकास के लिए कोई मदद मिलती है, और उसके साथ कोई स्ट्रिंग्ज एटेच्ड नहीं है, तो वह मदद नहीं लेनी चाहिए । दुनिया का इतिहास बताता है कि बाहर की मदद से देश के अन्दर के आन्दोलन या तहरीक या देश के विकास को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहा है ।

16.08 hrs.

[SHRI K.N. TIWARI *in the Chair*]

आप जानते हैं कि आजादी मिलने से पहले हमारे कई लोग देशकी आजादी के लिए हिन्दुस्तान से बाहर रहकर लड़ते थे और कई तरह की मदद लिया करते थे । उस जमाने में हम दूसरों से जो मदद लेते थे, क्या वह मदद खराब होती थी ? हिन्दुस्तान पर इंगलैंड का राज्य था, लेकिन लन्दन की छाती पर बैठ कर कई संस्थायें और हमारे कई देशभक्त देश की आजादी के लिये अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ

---

* Published in Gazette of India Extra-ordinary, Partt II. Section 2, dated 13.3.70

[श्री शिव चन्द्र झा]

लड़ते थे। उन को कई प्रकार की मदद बाहर से मिलती थी। क्या वह मदद खराब थी?

दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जब किसी अन्दरूनी आन्दोलन को, या विकास के काम को आगे बढ़ाने की जरूरत होती है, तो बाहर की मदद ली जाती है। जब अमरीका विकसित नहीं था, उस वक्त वहां पर अंग्रेजी पूंजी के द्वारा वहां की अर्थ-व्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली। इस में कोई शक नहीं कि बाद में कुछ खराबियां और धांधलियां हुई, जिन के कारण अमरीका ने अंग्रेजी पूंजी पर रोक लगाई। लेकिन यह तथ्य है कि अंग्रेजी पूंजी के कारण अमरीका के विकास में सहायता मिली।

रूस में भी एन० ई० पी०, न्यू इकानोमिक पालिसी, के जमाने में और उसके बाद बाहरी मदद की जरूरत हुई।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर): मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने मेरा यह बिल नहीं पढ़ा है। वह बिल तो कुछ और ही है।

श्री शिव चन्द्र झा: बुनियादी बात यह है कि क्या किसी बाहरी मदद से हमारे फंडामेंटल राइटस पर धक्का लगता है या नहीं। उस से इस फिजा में मदद लेने से, बाहरी एड लेने से कुछ ऐसा हो जाता है कि बाहरी एड से खामियां हो जाती हैं और हिन्दुस्तान की राजनीति में कुछ खराबी आने की सम्भावना है, इसलिए इस वक्त यह सोचना होगा कि चाहे कोई व्यक्ति हिन्दुस्तान में मदद लेता है या कोई पार्टी लेती है तो उस से कहां तक आपके देश के प्रगतिशील आंदोलन में फायदा होने को है? यहां पर यह बात साफ हो जाती है कि दुनिया में कुछ समाजवादी ताकतें भी काम कर रही हैं और समाजवादी ताकतों की तरफ से जो मदद मिलती है उस से न फंडामेंटल राइट को धक्का लगता है न विकास को धक्का लगता है, बल्कि हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है लेकिन अमरिकी साम्राज्य-वाद से जो मदद मिलती है यह निर्विवाद है कि चाहे कोई व्यक्ति नेता हो या किसी संस्था को मिलता हो, किसी रूप में मिलता हो, वह हमारे विचार को दूषित करता है लेकिन विचार की आजादी हमें आवश्यक है और यदि किसी का विचार खराब भी है, और यह उस का प्रचार करता है यहां पर जो हमें वह कदम नहीं उठाना चाहिए जिस से विचार की आजादी पर धक्का लगे। कल आप ने सुना होगा, जस्टिस होम ने कहा कि कितना भी रैडिकल और खराब विचार क्यों न हो, जब तक स्टेट को क्लीअर और पेटेंट डैंजर नहीं आता है तब तक हमें उस पर रोक लगाने का कोई हक नहीं है। जस्टिस होम ने कहा कि यदि कोई डिक्टेटरशिप की बात करता है और प्रचार करता है देश में तो संविधान और विचार-स्वातंत्र्य का तकाजा है कि उस को पूरी आजादी होनी चाहिए। लेकिन उस पर अमेंडमेंट ला कर जस्टिस ब्रैन्डाइज ने कहा कि यदि देश पर उस से खतरा आता है, देश के अस्तित्व पर खतरा आता है तभी स्टेट को हक मिलता है कि उस पर रोक लगाए। लेकिन जब तक वह खतरा नहीं आता है तब तक पूरी आजादी होनी चाहिए। इसी का ख्याल रख कर बाहर की मदद जो आती है या प्रचार जो होता है उस को हमें तोलना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो संस्थाएं यहां प्रचार करती हैं और वह हमारे विचार के खिलाफ हैं तो उस में हमें सोचना होगा कि कौन सी प्रगतिशील धारा से मदद मिल रही है और कौन प्रतिक्रिया-वादी धारा से मदद मिल रही है, इसका भी हमें ख्याल करना होगा। यह निर्विवाद बात है कि अमेरिका के नेतृत्व में जो प्रचार होता है, उस से जो मदद मिलती है उस से हिन्दुस्तान के मजदूर आन्दोलन और हमारी प्रगति के काम को धक्का लगने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ से जो मदद मिलती है उस से कोई खराबी नहीं आती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस का विरोध करता हूं।

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah): Mr. Chairman, Sir, if the purpose of the Bill of Shri Kanwar Lal Gupta is

to prevent the activites of some of our foreign governments doing injury to our national interests, then of course, the purpose of the Bill is a healthy one. But then, he should have brought a Bill in which we have got definite proof that certain forign governments are inimical to our interests. For exmple, if he had come before the House with a Bill whose purpose is to stop such activities of the Government of China, Red China, and the Government of Pakistan as are inimical to our intersts, who are not responding to our national overtures to bring about some understanding with them, if the purpose is to stop such countries from having their agents in this country and sending to this country money to injure our interests, certainly we would have supported this Bill of Shri Kanwar Lal Gupta. But unfortunatly the Bill has a wide range of certain insinuations also as if certain parties are interested in having foreign money to strengthen their parties in this country. We do not agree to this. India is vast country, and we have got friendly relations with all the big blocs of countries who are supposed to have been helping us in various respects.

If they have got their organisation and institutions here to strengthen the cause of our national interest, certainly we have no objection to it. Our External Affairs Ministry has already taken steps to close down all those cultural institutions which are functioning in an unauthorised manner. For example, the Soviet cultural institution in Tamilnadu was stopped, because it was unauthorised. But this Bill as it is, cannot be accepted by the House.

I come from a State where really Chinese interests are inimical to our interests and we are facing a situation where we can say that the Indian security is at stake. We know that Chinese money is flowing and also through Nepal. If such a non-official Bill seeking to prevent activities by countries inimical to us is brought before the House, we can support it. In its present form, this Bill cannot receive the support of the House.

Our country has friendly relations with several big and small countries. We do not want to antagonise our friendly relations with them by taking a one-sided view of things. We know that West Germany has got certain cultural institutions in India. We have studied their activities and do not agree that their activities are inimical to our interest.

We are not aware of the fact that certain individuals are being financed by foreign countries, except that I have got definite information that countries like Pakistan and China are trying to create agencies of their own to injure our interest. If a Bill is brought by Mr. Gupta to prevent such things, I can support it, But we are not prepared to accept this omnibus type of Bill which prevents even friendly countries from helping us and which might be interpreted as hostile action on our part. We have to maintain very fine diplomatic relation with countries, big and small. We are a developing country with a population of 54 crores of poverty-stricken people and our monetary resources are limited. Therefore, we have to seek the help of friendly countries, big and small. Therefore, I strongly oppose this Bill and I cannot support it in its present from.

** SHRI E.K. NAYANAR (Palghat): Mr. Chairman, Sir, I would like to speak in Malayalam. The Bill introduced by Shri Kanwar Lal Gupta is inadiquate. It is said in his Bill that foreign aid adversely affects the souereignty and the independence of the country. That is correct. It is not specifically stated in this Bill as to how the entry of such foreign money into this country can be stopped. Foreign money does come to our country, and we have also established undertakings in collaboration with foreign countries. We have got money in our country under PL 480 from America. Our Home Minister Shri Chavan has himself said in answer to questions in this very House that during the 1967 elections foreign money was the utilised. It was passed in our papers that accounts about the utilisation by America

** The original speech was delivered in Malyam.

[Shri B.K. Nayanar]

of about Rs. 30 crores received in this country under PL 480 have not been cleard. During the 1962 elections, the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru went to Bombay from where Shri V. K. Krishna Menon was seeking election. At that time Mr. Nehru himself had vehement by criticised the inflow of foreign money into our country and its use in our elections. This had created a lot of sensation in our country at that time. What Shri Kanwarlal Gupta has said in his speech, that foreign money is behind the national troubles in our country, is correct. Not only through cultural Centres of Soviet Union and China alone what he Daid but also through organisations like the Ford Foundation of America and other institutions set up by West Germany and other Western countries, foreign money is coming to our country. Mr. Gupta is not seeing this. The only object of Shri Kanwarlal Gupta's Bill is that accounts of foreign money coming to our country should be maintained. Even in this respect the Bill is inadequate. Everybody knows money is received in our country through Christian missionaries. Certainly everybody knows that money is received here for religious proapanda. But our country dose not believe in only one religion; it is a secular State. Being a secular State there should be freedom for the spread of any religion. Our State is not like Pakistan or any other State where all the people belong to one relegion. All religions should have full liberty to propagate their tenets in our country. We should remember that organisations like the Ramakrishna Mission go to America and other countries to propagate the Hindu religion. Therefore, we should not do anything which goes against the secular spirit of our country. But religion should not be allowed to enter into our politics.

Another point is about the literature that is coming to our country from America, Russia, and other countries. It is said that through books and literature foreign money is coming to our country. This is not a thing which started recently. Books from Socialist and Capitalist counries are necessary in our cnuntry. Only through them will we be able to expand our knowledge and learn about the latest technical developments in other countries. Therefore it is wrong to say that through books foreign money is coming to our country. Any attempt to stop such books to our country will be a step in the wrong direction. For example, even words like Socialism and Communism were not first coined in India. They have come to India from foreign countries. Anything good that has come from foreign countries should not be rejected just because it has come from foreign countries. Even during the days when our country was under British rule, books on socialism, Communism and Capitalism were in circulation here. Any attempt to stop these books coming to our country on the ground that it is another way for entry of foreign money is not acceptable to us and I would say that it would not be a correct step. Truly speaking, it is not through these books that foreigners exert their influence on us. Actually it is the trade agreements entered into by foreign and Indian monopolists that are responsible for foreign influence in this country. After attaining independence we are indebted to foreign counirtes to the extent of Rs. 6500 crores. We know that a major portion of this has been obtained from America and Britain. If we want to stop the inflow of foreign money into our country we must become financially sound so that we will not have to enter into trade agreement with foreign companies. For example, Egypt which has attained independence is not a Socialist or a communist country like Russia or China but still they have nationalised all foreign capital. In our country there is foreign capital; there are foreign companies doing business and through them those countries are able to exert influence on us. Because this Bill does not provide for making our country financially sound so much so that we need not take the help of foreign companies, this Bill is inadequate. The existence of foreign capital in our country affects even our sovereignty and we should find out ways how we can do away with foreign capital. Without attaining self-reliance in the matter of finance, we will not be able to face the challenge posed by foreign capital in our country. Instead of trying to stop the flow of foreign literature into our country and curb the work done by Christian missionaries, we should try to evolve an independent finanancial system. For that, this Bill is inadequate.

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili) : Mr. Chairman, Sir, one cannot have any objection to the object of the Bill but the way it has been translated into the Bill seems to create certain doubts in my mind.

First of all, I feel that the way it has drafted it is largely defective. For instance, it talks of persons, organisations etc. God knows to whom it refers. Normally, that is not done in a legislative piece of work. When you impose certain restrictions and obligations on persons or organisations, you have to be definite about them. This Bill lacks that precision and that is sufficient to throw this Bill out.

Apart from this technicality, I feel that by and large there are two aspects implicit in this Bill. The first fundamental question is whether it is desirable to recives any foreign aid on behalf of other Governments or agencies by individuals or association in this country. The second one is whether the receipt of such aid influences the people at large. It must be viewed from these two aspects.

So far as the first aspect is concerned, we have to draw a distinction. If there is any aid from Governments or educational institutions abroad for libraries and eduacational institutions in the country, I do not find any particular reason why we should have objection to that. By and large what idelogy we have to develop and what polity we have to evolve, ultimately is to be decided by the national will. To assume that any amount of influence from outside will have an imegrative impact on this country—it may have certain marginal influence—is to assume that we have perhaps not matured—a conclusion I protest against. We are competent to decide for ourselves what policy we must adopt ultimately. In that process it is but natural that system all over the world will try to influence. This process is not only going on in this country but is going on in all the underdeveloped countries; the only difference—which I want to emphasize—is that when it is a question of national dignity they stand up in the African countries, whether it is America or Russia, and say, "You are interfering in our affairs; please go away." They draw upon the aid but they never succumb to its influence. Therefore aid by itself is not such a wrong thing. If we develop a strong will that will be a remedy.

Some friends have referred to the missionaries and in that context, unfortunately, secularism has also been brought in. Secularism is a concept which we have to believe in. If any outside agencies try to influence our religion, I object to it because ultimately that will have certain repercussions. But we have to deal with it on a different level and not in this perfunctory manner.

Similarly, political parties. We have had a lot of discussion about these things. The Home Minister has also come forward with certain proposals. We have to deal with political parties on the political level.

Next comes the question of maintenance af accounts. I feel, whatever imposition you make, as the Bill itself states there is certain indirect aid and how that indirect help can be detected. The very nature of indirect help is such that you can never detect it. If you cannot detect, there is no question of maintaining accounts. Therefore, I feel that it only has a nuisance value and nothing beyond that.

Ultimately the answer for all these things is that we have to develop our national will and character. That is the solution. Meanwhile, these marginal interferences are bound to take place. with these remarks, I oppose this Bill.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि बाहर से रुपया आता है—चाहे वह लिट्रेचर की शक्ल में हो और चाहे ट्रैक्टर की एजेन्सी लेकर रुपया कमाया जाये पार्टी इन्ट्रेस्ट के लिये और चाहे फारेन टूर्स की शक्ल में रुपया हो या फिर सी०आई०ए० की मार्फत रुपया हो। बहरहाल है रुपया जरूर। यह बात तो हमें पता है और उसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। सोल्हवीं सदी के शुरू में आपने देखा कि हमारा देश इसलिए गुलाम बना क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा शरीफ आदमी

[श्री रणधीर सिंह]

थे और हम बहुत जल्दी दूसरों के ऊपर एतबार कर लेते थे । इसीलिए ईस्ट इंडिया कम्पनी ने सारे हिन्दुस्तान पर कब्जा कर लिया । ऐसी बात नहीं है, जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि हमें अपनी ताकत और यूनिटी पर कोई शक हो लेकिन फिर भी हमको कोशिश जरूर करना है । हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, इंटेलिजेन्स की जगह भी गड़बड़ है और फौज में भी हमने सुना है कि बहुत ज्यादा भेद की बातें पीकिंग रेडियो और पाकिस्तान रेडिओ से सुन ली जाती हैं । तो इस किस्म की जो बातें हैं उनसे हमारा देश बदनाम होता है । इसलिये कोई न कोई चीज है जरूर । और उससे हमारे देश की यूनिटी, इन्टेग्रिटी और सावरेन्टी पर बड़ा भारी असर पड़ता है । यह बात नहीं है कि होम मिनिस्टर की कोई स्लैकनैस है । लेकिन उसके बावजूद मर्ज बढ़ता गया ज्यूं-ज्यूं दवा की । हम दवा कर रहे हैं और मर्ज बढ़ता जा रहा है । कोई रुस जाता है तो फिर अमरीका से भी दावतनामा आता है कि हमारे यहां भी आइये । अगर कोई चीन जायेगा तो तैवान से भी दावतनामा आयेगा । मालूम होता है जैसे कि पब्लिसिटी एजेन्ट हैं । अगर कोई ईस्ट जर्मनी जायेगा तो साथ-साथ दावतानामा आयेगा कि इजरायल भी देखियेगा ! ईस्ट जर्मनी जायें कोई बात नहीं लेकिन मालूम नहीं ईस्ट जर्मनी में क्या नयी बात हो गई है जिसके लिए इतनी तमन्ना होती है ।

अब रही बात एकाउन्टस की तो एकाउन्टस जरूर होने चाहिए । एकाउन्टस तो मां बाप के भी होते है और यह तो बाहर का कन्टैक्ट हैं । एक है अमेरिकन शैडो, मैंने उसको पढ़ा और उसको पढ़कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । इसी तरह से और भी शैडो हैं । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता नहीं तो बुरा मानेंगे । सारा कन्ट्री, क्या नेफा और क्या बंगाल, सब भरा पड़ा है और वहां बड़ी घिनौनी बातें हैं । इसलिए हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है । मैं गुप्ता जी से कहूंगा कि वे अब इस बात को और आगे न बढ़ायें । होम मिनिस्टर की नोटिस में वे इस बात को ले आये हैं जिससे उनका पर्पज सर्व हो गया है । यह जरूर है कि अब दूकानदारी बहुत बढ़ गई है और हमें पता है कि इस हमाम में सारे ही नंगे हैं । कोई भी पार्टी हो । मैं नाम नहीं लेता लेकिन बड़ा भारी जुलूस निकलता है, बड़ा भारी मुजाहरा होता है लेकिन पता नही कहां से पैसा आता है । इसी तरह से अखबार चल रहे हैं । मैं नाम लूंगा तो नाराज हो जायेंगे । एक आदमी ओवरनाइट लखपति बन जाता है, भगवान जाने कहां से पैसा आ गया । इसी तरह से फ्रीडम आफ एशिया, पता नहीं क्या बला है ?........ (व्यवधान)...... पूरा फ्लड है लिट्रेचर का और उसमें दुनिया भर का चीप मैटीरियल भरा हुआ है । लेकिन आदमी दुकान चला रहे हैं । मुझे पता है कि लोगों को मेहनताना मिलता है कई कई हजार, किसी इम्बेसी की मार्फत वह मिलता है । लोग पकड़े गए हैं । इसलिए इस देश में जो हो रहा है उसकी तरफ, मैं आपकी मार्फत होम मिनिस्टर साहब से चाहूंगा कि अपनी नजर रखें । मैं तो यहां तक जाऊंगा कि अहमदाबाद के लिए भी मुझे शक है कि वहां पर जो रायटस हुए उसमें भी किसी का हाथ था । सारे देश में हिन्दू और मुसलमानों को लड़ाने की एक साजिश चल रही है और उसके लिए बाहर से रुपया आता है । हमें देखना है कि उसका सोर्स किस तरह से बन्द किया जाये । बड़ी बड़ी शक्ल में पीस कोर के नाम से और दूसरे नामों से आते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं । लेकिन उस के उपर भी हमें अपनी नजर रखने की जरूरत है क्योंकि होसकता है शुरू में वह चीज हमको दवाई नजर आये लेकिन बाद में जहर बन जाये । मैं आखिर में गुप्ता जी से कहूंगा कि वे होम मिनिस्टर की नोटिस में इस बात को ले आये हैं उनका मतलब सर्व हो चुका है अब इसके उपर उनको डिवीजन की बात नहीं सोचनी चाहिये । उनकी बात पुरी हो गई है, अब वे इसको विदड्रा कर लेंगे । आपने मुझे जो टाइम दिया उसके लिए आपका बड़ा मश्कूर हूं ।

श्री शिवनारायण (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने जो रेजोल्यूशन इस हाउस के सामने पेश किया है उसके सम्बन्ध में इन लोगो ने जो पंवारा गाया है उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें यह सिधी सादी बात है कि होम मिनिस्टर को इस बात की नालेज होनी चाहिए कि किसको कहां से कितना पैसा मिला । इसका हिसाब परिपक्व मिलना चाहिए। मैं नहीं समझता इसमें कौनसी गुनाह की बात है ; मैं होम मिनिस्टर साहाब को आगाह करना चाहता हूं कि इस देश में अंग्रेज बनिया बनकर आये थे लेकिन उन्होंने दो सौ वर्ष तक हमको गुलाम बनाये रखा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन चीजों से आप इस देश को बचाने कि कोशिश कीजिए । इस बिल में एक बड़ी सिंपुल सी चीज है कि एकाउन्ट रखे जायं । जो कोई भी यहां पर कल्चरल पर्पज या किसी ध्येय से आये तो उसमें यह देखने की जरूरत होती है कि वह उसी पर्पज को सर्व कर रहे हैं न कि यह कि हमारे देश के खिलाफ कोई कांसपिरेसी करें। यह बड़े खेद की बात होती है कि जो खबर हमको होम मिनिस्टर भी नहीं देते हैं वह खबर रात को पाकिस्तान के रेडियो से ब्राडकास्ट हो जाती है । यह वीकनेस और स्लैकनेस इस गवर्नमेन्ट की है । आजकल कश्मीर, पंजाब हरयाणा, दिल्ली' बिहार उत्तर प्रदेश, बंगाल केरल हर जगर पर माइनारिटी गवर्नमेन्ट है जैसे कि यहां पर है ... (**व्यवधान**) ... यह आपका नकशा है ... (**व्यवधान**) ... मैं देशभक्त होने के नाते अपना परम कर्त्तव्य समझता हूं कि इस सरकार को सावधान करूं और ठीक करूं ताकि कल को अगर हम वहां पर पहुंचे तो जो बात हम कहते हैं उसको निभायें । मैं इनकी तरह से लफ्फाजी की बाते नहीं करता हूं। हम आपसे चाहते है कि जितनी रकम आये—हम आपको रोकते नहीं हैं कि मत लीजिए लेकिन उसकी निगरानी होनी चाहिए। इसबिल में जो है वह कोई गुनाह नहीं है और मैं समझता हूं किसी भी सदस्य को उसपर एतराज नहीं होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ) : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो बिल यहां पर रखा है उसकी भाषा पढ़ने से बड़ी अच्छी मालूम होती हैं । माननीय सदस्य की पार्टी का उनकी विचारधा के लोग जो भी चीज लाते हैं वह उपर से भले ही अच्छी लगे लेकिन उसके अन्दर काफी गड़बड़ बाते होती हैं । ये यहां पर ढोल पीटते हैं लेकिन यहां पर जो फारेन मिशनरीज हैं वह गरीबों को इसाई बनाती हैं। कितनी इस प्रकार की संस्थायें यहां चल रही हैं जिनको कि बराबर एड मिलती रहती है । उसके अलावा यहां पर कितने ही पब्लिक स्कूल चल रहे हैं ,कितने ही कानवेन्ट स्कूल चल रहे हैं। ये स्वदेशी का नाटक रचते हैं लेकिन इनके बच्चे कानवेन्ट स्कूलों में पढ़ने जाते हे ये बनते है स्वदेशी लेकिन इंग्लिश पिक्चर देखने जाते हैं जहां तक एकाउन्टस का सवाल है , भारत सेवक समाज का एकाउन्टस जा सकता है , राजनीतिक संस्थाओं के एकाउन्ट देखे जा सकते है लेकिन गुरू गोलवाल्कर के पास करोड़ों जमा है आज तक किसने पूछा कि कैसे इतना चन्दा इकट्ठा हुआ है और कहां से इतना रुपया आता है तोड फोड के लिये ।

अभी ईसाई मिशनरीज के लिये कहा गया। मैं कहना चाहता हूं कि उनके दिल में चाहे कोई गड़बड़ हो, लेकिन उन्होंने यहां पर शिक्षा को बढ़ाया । अकाल के समय मे गल्ला मंगा कर गरीबों कि सहायता की । मैं जानना चाहता हु कि क्या यहां पर भी कोई संस्था आपने चलाई गरीबों की सहायता करने के लिये ? क्या आपने कभी हरिजनों को छाती से लगाया ? मानता हूं कि ईसाई मिशनरीज ने हरिजनों और गरीब लोगों को ईसाई बनाया मुसलमानों ने मुसलमान बनाया । आप मुसलमानों को बुरा भला कहते है, लेकिन आपके दिल में क्या है ; क्या कभी भी आपने उन लोगों को छाती से लगाया ;

श्री कंवर लाल गुप्त : बिल पर बोलिये।

श्री नाथूराम अहिरवार : बिल पर ही बोल रहा हूं । आप मिशनरीज पर बन्दिश लगाना

[श्री नाथूराम अहिरवार]

चाहते हैं। आपने बतलाया कि जितने भी पब्लिक स्कूल हैं यहां पर उनको विदेशों से ग्रांट मिलती है। जहां तक वह शिक्षा का काम करते हैं. संस्कृती को बढ़ाने का काम करते हैं, वह अच्छा है। लेकिन अगर कोई मिशनरी तोड़ फोड़ का काम करता है तो उसके बारे में पार्टिकुलरली आपको बिल में लिखना चाहिये। उदाहरण देना चाहिये कि फलाने फलाने संस्था ने देश के लिये अहित का काम किया है। मैं कहता हूं कि अगर आप कहते कि ऐसे लोगों और ऐसी संस्थाओं पर बन्दिश लगानी चाहिये, उनके दफ्तर को बन्द करना चाहिये तब तो ठीक था, लेकिन आपने ऐसी कोई भी मिसाल नहीं दी है कि कौनसी संस्थाओं पर रोक लगनी चाहिये, चाहे वह अच्छा काम करती हों या बुरा।

कहने के लिये बिल का जो मतलब है वह तो ठीक है, लेकिन जो मंशा उसके पीछे है मैं उसका विरोध करता हूं। माननीय सदस्य को चाहिये कि किसी पार्टिकुलर संस्था का नाम लेते कि उसका हिसाब रक्खा जाय और उसको बन्द किया जाय, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हर एक संस्था को हिसाब रखना चाहिये चाहे वह विदेशी हो या देशी हो। आज हमारे देश में ऐसी संस्थायें हैं जो हिन्दू धर्म के नाम पर चलती हैं, हिन्दू संस्कृति के नाम पर चलती हैं। उनको भी अपना हिसाब देना चाहिये। अपने देश की संस्थायें भी विदेशों से पैसा लेती हैं। उनको भी अपना अकाउंट रखना चाहिये और उन पर भी बन्दिश लगनी चाहिये। इनके बारे में भी आपको बिल में कहना चाहिये था और उनका नाम भी लेना चाहिये था।

इन शब्दो के साथ मैं इस बिल का विरोधी करता हूं क्योंकि उस की मंशा ठीक नहीं है।

श्री स. मो. बनर्जी (कानपुर): सभापति महोदय, जहां तक इस विधेयक के मकसद का सवाल है, वह बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं कि श्री कंवरलाल गुप्त ने एक बहुत बड़े सवाल पर विचार करने का मौका हम लोगों को दिया है। लेकिन यहा पर प्रश्न एक है कि पी. एल 480 के बारे में हमने हिसाब मांगा था, मगर आज तक वह हिसाब हम लोगो के पास नहीं आया है। मंत्री महोदय को यह मालूम है कि पिछले चुनाव में या उससे पहले के चुनाव में पी एल 480 की मदद से काफी राजनीतिक पार्टियों को पैसा दिया गया। उसके लिए बार बार हम लोगों ने कहा कि जांच होनी चाहिए। मंत्री महोदय ने यहां पर बयान दिया था कि हां, वह जांच करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के दर्म्यान कितनी पार्टियों को पैसा मिला है और वाकई में उन्होंने विदेशी पैसा लिया या नहीं। इस लिये पहले हम पी. एल 480 को कंट्रोल करें जो देश में पूरे देश की राजनीति को गन्दा कर सकता है।

दूसरा सवाल है सी. आई. ए. ऐक्टिविटीज के बारे में, जो पैसा उनका चल रहा है, उसके बारे में। आपको मालूम है कि जब यह फैसला लिया गया कि शुगर के कारखानों को, चीनी के कारखानों को नेशनेलाइज किया जाय और जब यह हुआ कि मि० चन्द्रभानु गुप्त के साथ बहुमत नहीं रहा और उनकी सरकार के गिरने की बात चली, तब अखबारों ने सुर्खी निकली कि सी. आई. ए. का रुपया और शुगर मैग्नेट्स का रुपया पैसा काफी चला गुप्त मंत्रिमण्डल को कायम रखने के लिये यह बात सही है या गलत हैं इसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। (व्यवधान) यह अखबार की खबर थी।

श्री पीलू मोदी (गोधरा): गरीबों के पास बहुत पैसा है।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा): वह अपने देश का पैसा है परदेश का पैसा नहीं है।

श्री स. मो. बनर्जी: आपने सुना नहीं

वह सी. आई. ए. का पैसा था । उस समय देशी और परदेशी दोनों पैसे चले । चाहे वह पैसा देशी चला हो या परदेशी चला हो दोनों का मकसद एक ही है ।

जितनी भी संस्थाएँ ऐसी हैं, जो कल्चर के नाम से या एजुकेशन के नाम से हैं, मैं चाहता हूं कि उसके पैसे पर रोक लगाई जाय, उनके अकाउन्ट्स बाकायदा देखे जायें। अगर आप समझते हैं कि इस विधेयक को लाकर वह रुक जायेगा तो इस तरह से वह रुकने वाला नहीं है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में विश्वास दिलायें ।

यह सही बात है और मैं इस बात को मानता हूं कि विदेशी मनी आज हमारे देश में आ रहा है । जब इस्ट इंडिया कम्पनी की शक्ल में अंग्रेज लोग कालीकट के किनारे आये थे तब वह व्यापारी बन कर आये थे तिजारत करने के नाम पर हमारे सामने आये। उस वक्त हम सोते रहे और आखीर में उनका झंडा लहराने लगा। इसलिए हमारे देश के चलाने वालों को सरमायेदारों और विदेशी पैसे पर निर्भर नहीं रहना चाहिये । हमको मजदूरों के पैसे से चुनाव लड़ना चाहिये । हमको विदेशी पैसों की जरूरत कभी नहीं होगी । स्वदेशी पैसे को इस्तेमाल किया जाय तो हमको कभी भी बाहर के पैसे की जरूरत नहीं होगी। हम देखते हैं कि सी आई ए की ऐक्टिविटीज देश में बढ़ती जा रही है । इसके बारे में बाकायदा जांच होनी चाहिये । पी एल 480 का कितना पैसा चुनाव में खर्च हुआ इसकी जो जांच की है मंत्री महोदय ने उसको हमारे सामने रखें ।

अन्त में मुझे कहना यह है कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी एक चीज रह जायेगी । कल्चरल फंडस के नाम से जो पैसा विदेशों से आया करता है कल्चरल यूनिट्स और कल्चरल आर्गेनाइजेशन्स के नाम से जो पैसा आता है उस पर रोक लगा दी गई है यह ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब से उस पर रोक लगी है यू एस अम्बेसेडर जो हिन्दुस्तान में हैं, मि. कीटिंग, वह प्रेस कांफरेंस कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इस इन्स्टिटयूशन्स को हमने इस वास्ते बनाया । इसके बारे में मतभेद था काबीना में । इस पर वह बयान देते हैं । मैं पूछना चाहता हूं की उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वह इस पर बयान दे ।

इस लिये मैं श्री गुप्त से निवेदन करूंगा कि अगर मंत्री महोदय इस बारे में आश्वासन दें तो वह विधेयक को वापस ले । लेकिन आश्वासन को अमली जामा पहनाने की जरूरत होगी । तभी तमाम चीजें ठीक हो सकेंगी ।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : सभापति महोदय, इस बिल के बारे में जितनी चर्चा हाउस में हुई है उसमें किसी को सिद्धांत रूप से इसमें आपत्ति हुई हो ऐसा नहीं लगता है । इसमें कोई खास आपत्ति होने का कारण भी नहीं है । यद्यपि मैं मानता हूं कि सिद्धान्त रूप से इसमें यह बिल अच्छा है, फिर भी जितना काम्प्रिहेन्सिव इसको होना चाहिये था, शायद यह उतना नहीं है । मान लिजिये यहां कोई मिशनरी है, जो कि परदेश से सम्बन्धित हों, जो कि होते हैं, वह अपनी मिशनरीज को बढ़ाने के लिये अगर रुपया लाना चाहें तो उन पर इस विधेयक का एफेक्ट तो पड़ता ही है, क्योंकि किसी तरह से उनका वह रुपया नहीं आयेगा । लेकिन कानून की दृष्टि से इसको अधिक काम्प्रिहेन्सिव बनाने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं और सरकार से बिनंती करता हूं कि यदि वह इसके प्रिंसिपल को शामिल कर लें तो वह ज्यादा विचार करके एक काम्प्रिहेन्सिव बिल हाउस के सामने ला सकते हैं और उनको लाना चाहिये ।

अभी श्री बनर्जी ने कहा कि यह कानून बना देने मात्र से सब कुछ बन्द नहीं हो जायेगा । यह बात सही है क्योंकि जब कोई भी कानून बनता है तो उससे सारी बुराइयां, जिनको रोकने के लिये कानून बनाया जाता है, रुक नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी उन पर कुछ प्रति-

[श्री स. मो. बनर्जी]

बंध और कुछ नियंत्रण तो आ ही जाता है, और इतना ही हम विशेष रूप से कर सकते हैं।

आज पाश्चात्य देशों से जो पैसा आता है वह एम्बैसीज की मारफत भी आता है। पिछली बार यहां काफी गरमी पैदा हुई थी जब रशियन अम्बैसेडर भुवनेश्वर गये और उन्होंने वहां की सरकार को गिराने की कोशिश की वहां उन्होने पैसा भी खर्च किया। पता नहीं यह बात कहां तक सच है या गलत है। यह तो सरकार ही पता लगा सकती है। इस तरह से भारत की कोई भी एम्बैसी यदि पैसा लाती हो तो आज उसको एक दूसरा लाभ भी होता है। मुझे पता लगा है कि डिवैल्यु-एशन के पहले आफिशली जहां एक डालर की कीमत पांच रुपया हुआ करती थी, डिवैल्युएशन के बाद वह साढ़े सात रुपया हुई और साल भर पहले ओपन मार्किट में उसकी प्राइज साढ़े नौ और दस रुपये थी लेकिन वर्तमान बजट के पहले जहां एक डालर की कीमत ग्यारह सवा ग्यारह रुपये थी वहां वह पांच सात रोज के अन्दर दस रोज के अन्दर चौदह रुपये से उपर चली गई है। यदि इतना अधिक एकदम फर्क पड़ता है तो इसका अर्थ यह है कि करोड़ों रुपया देश का बाहर गया हैं और उसके बदले में फारेन करेंसी का भी करोड़ों आया है। अगर उसका हिसाब नहीं रखा जाता है, उसको किताबों के अन्दर नहीं दिखाया जाता है और सरकार की मार्फत वह नहीं आता है तो इसका मतलब होता है कि एक डालर के बदले उनको चौदह रुपये अनआफि-शली मिलेंगे वर्ना साढ़े सात ही मिलेंगे। देश का इतना अधिक रुपया जो अनआफिशली बाहर चला जाता है, इस पर भी नियंत्रण लगाने की बहुत जरूरत है। जो इस तरह बाहर से रुपया आता है उससे जो काम होते हैं उन कामों को भी हमको देखने का मौका नहीं मिलता हैं। इस तरह से बाहर से आया हुआ रुपया भी हमारे विकास के कामों में आता है और मिश-नरियों के पास जो रुपया आता है वह धर्म परिवर्तन के कामों में काफी आता है। एम्बै-सीज के पास जो रुपया आता है उससे वे अपने काम सस्ते में चला लेती हैं। हमारी अराष्ट्री-यता बढ़ाने के अन्दर भी वे लोग काम कर रहे हैं। यदि आफिशली रुपया आएगा तो हमारे रुपये की कीमत भी अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में कम नहीं होगी और यदि अनआफिशली आएगा तो जैसे अभी बताया है कि एक डालर की कीमत चौदह रुपये तक हो गई है और अगर इसी तरह से यह चीज चलती रही तो अन्तर्रा-ष्ट्रीय मार्किट में आपका रुपया आठ आने के बराबर रह जाएगा और बाद में विदेशों से हम पर फिर से वही असर पड़ना शुरू होगा कि आप डिवैल्युएशन करो फिर चाहे वह असर वर्ल्ड बैंक की तरफ से पड़े या किसी दूसरे देश की तरफ से। जिन देशों ने कर्जा दे रखा है, उन्होंने जितना कर्जा हमें दिया है और जिस भाव से दिया है उसको जब हम वापिस लौटा-येंगे तो हमारे रुपये का अवमूल्यन होगा और उस हिसाब से हमको उन्हें रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। इस सब पर अच्छी तरह से सोच विचार करके कानूनी दृष्टि से जितना अच्छी तरह प्रतिबन्ध हम लगा सकें, हमको लगाने का प्रयत्न करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि इससे हमारे रुपये की कीमत को स्थिर करने में भी मदद मिलेगी और हमारे राष्ट्रीय काम जो हैं, निर्माण कार्य जो हैं, उनको उन्नत करने में भी हमको मदद मिलेगी।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, हम दोनों के बिल रह गए है। हमें उनको पेश करने की इजाजत आप दे दें। एक सैकिंड में काम हो जाएगा।

सभापति महोदय : आपके बिलों को हम साढ़े छः बजे ले लेंगे और तब आपको उनको पेश करने की इजाजत दे देंगे।

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तोड़गढ़) : सभापति महोदय, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कंवर लाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने

देश की इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर देशवासीयों का ध्यान खीचा है और एक प्रस्ताव गैर सरकारी ढंग से विचारार्थ यहां प्रस्तुत किया है ।

यह सही है कि आज के इस विश्व के तनावपूर्ण वातावरण में और अन्तराष्ट्रीय स्थिति में हम एक दूसरे से आइसोलेट हो कर नहीं रह सकते, हम एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकते । कुछ राष्ट्र हैं जो बहुत उन्नति शील हैं और कुछ दूसरे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं । टेक्नीकल नो हऊ जानने के लिए और इसके अलावा भी हमें एक दूसरे के साथ सहयोग की जरुरत पड़ेगी । जहां तक इस बिल के मंशे का सवाल है, अगर मैं सही समझा हूं तो मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य का मंशा यह रहा होगा कि विदेशों से जो नगद धन हमारे देश में आता है व्यक्तीयों के माध्यम से या संस्थाओं के माध्यम से, वह नहीं आना चाहिये । मैं सहमत हूं कि किसी भी राष्ट्र का अगर सम्मान सुरक्षित रह सकता है, कोई भी राष्ट्र यदि आजादी के साथ जिन्दा रह सकता है अपनी स्वतंता की रक्षा कर सकता है तो केवल अपने पैरों पर खड़ा हो कर ही कर सकता है । हमने बरसों तक अपने आदमीयों का पेट भरने के लिए पी एल 480 के अन्तर्गत करोड़ों रु० का अनाज बाहर से मंगाया है । इसका परिणाम यह हुआ है कि हम में परावलम्बन की आदत पड़ गई है । कोई भी राष्ट्र अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करके, अपनी इकोनोमी को ठीक करके और कम खा कर और अधिक मेहनत करके सुरक्षित रह सकता है और अपनी आजादी को स्थायी बना सकता है ।

जो हमें विदेशों से मदद मिलती है, उसकी हालत क्या है । कोई भी विदेशी देवता नहीं है । हर देश के दिमाग में अपने अपने ग्रुप या अपने अपने दल बनाने की एक मनोवृति है, फिर चाहे वह पश्चिमी राष्ट्र हो या पूर्व का हो, चाहे वह डैमोक्रेसी में विश्वास करने वाला राष्ट्र हो या किसी दूसरी आइडियोलोजी में विश्वास करने वाला हो । यह देश आज अपने ढंग से और अपने हितों को सर्वोपरि रख कर सहायता देता है । इस वास्ते हमें देखना होगा कि किस मोटिव को सामने रख कर देश सहायता देते हैं । बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं । ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर विदेशी सौदागरों के रूप में गए और अन्त में वहां के मालिक बन गए । अंग्रेज हमारे देश में किस प्रकार आये । हम से मदद लेकर हमारी साहायता करने के बहाने आए । उन्होंने मुगल सलतनत के सामने अपनी सहायता का हाथ बढ़ाया और जब यह हाथ स्वीकार कर लिया गया, तब वे धीरे धीरे यहां के मालिक बन गए । इस लिए यह अत्यन्त आवश्यक अर महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने देश में विदेशी धन को अधिक महत्व न दें । विदेशी धन हमारे देश के अन्दर जितनी अधिक माता में आएगा चाहे संस्थाओं के माध्यम से आए चाहे राजनीतिक दलों के माध्यम से और राजनैतिक दलों के माध्यम से आना तो और अधिक खतरनाक है, उतनी ही ज्यादा हम में परावलम्बन की भावना पैदा होगी । आज हो क्या रहा है । राजनीतिक दृष्टि से भी हमारे देश की पार्टियों को विदेशों द्वारा प्रभावित करने की चेष्टायें की जा रही हैं । अलग अलग देश अपने अपने ढंग से हमारे यहां की राजनीति पर, हमारे देश की अर्थ नीती पर परभाव डालने की चेष्टा कर रहे हैं । इस लिए मैं चाहता हूं कि हम कम खायें, हमारा राष्ट्र परिश्रम अधिक करे, हम अधिक ताकत से अपना विकास करें, अपनी अतीत की संस्कृति को पुनः जीवत करें । विदेशी सहायता पर अवलम्बित रहने की जो हमारी आदत पड़ गई है, उससे हम बाज आएं ।

बीस बरस में हम अपने देश का नक्शा जैसा चाहते थे वैसा बना नहीं पाए हैं । इसलिए नहीं बना पाए कि हम अपने साधनों का, अपनी प्राकृतिक सम्पदा का अपनी मेहनत का उपयोग नहीं किया । द्वितीय महायुद्ध के बाद जर्मनी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया

[श्री ओंकार लाल बोहरा]

है फिर से शक्तिशाली राष्ट्र बन गया हैं, जापान ने भी बड़ी तरक्की कर ली है लेकिन हम नहीं कर पाये हैं । इसका कारण यह है कि हम अपनी कुव्वत, अपनी ताकत पर भरोसा नही करते ।

गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ये जो बुनियादी तत्व है, इनका नया बिल बनाते समय विचार किया जायेगा । इसको देखते हुए श्री गुप्त जी अपने इस बिल को वापिस ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। उनका जो उद्देश्य था वह पुरा हो गया है । वे चाहते थे कि इस पर चर्चा का मौका मिलें और देश का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट हो। उनका यह उद्देश्य पूरा हो गया हैं । मैं चाहता हूं कि विदेशी धन हमारे देश में न लाया जाए, फिर चाहे वह लिट्रेचर के माध्यम से आए चाहे सांसकृतिक आयोजन के माध्यम से आए । हमको देश की इकोनोमी स्वयं अपने प्रयत्नों से और अपनी मेहनत से दृढ़ करनी होगी । हमें देश को परावलम्बन से हटा कर स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करना होगा । एक स्वाभिमानी राष्ट्र का यही तकाजा है । देश में विदेशी धन न आने दिया जाए, इसी में हमारा हित है ।

मिशनरियों के माध्यम से गरीब आदमियों के साथ खिलवाड़ हो रही है । हजारों गरीब आदमियों को धर्म परिवर्तन के लिए लाचार किया जा रहा है। इस वास्ते वे धर्म परिवर्तन पर मजबुर हो जाते हैं कि हमने उनकी चिन्ता नहीं की गरीब भाईयों की, हरिजन भाईयों की, पिछड़े हुए भाईयों की चिन्ता नहीं की। आखिर वे चाहते क्या है ? उनकी जो बुनियादी जरुरतें हैं, वे अभी पूरी नहीं हुई हैं । इसीलिए व प्रलोभन में आ जाते हैं और विदेशी धन से प्रभावित हो जाते हैं । धन चाहे किसी भी माध्यम से आए, वह हमारे सांस्कृतिक विकास बौद्धिक विकास शारिरीक विकास राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए एक चुनोती है । नया बिल प्रस्तुत करते समय गृह मंत्री जी विस्तृत रुप से इन सब बातों पर विचार करे । टैक्नीकल नो हउ का उपयोग किया जाए, इससे मैं इन्कार नही करता हूं । हम आईसोलेट न रहें । विदेशों से हमारे दूसरी तरह के सम्बन्ध रहे आज के संसार में कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से अलग अलग नहीं रह सकता है । उनको एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है हम को भी जिंक आदि बाहर से लेना पड़ता है । दूसरी चीजे भी हम ले सकते है । लेकिन व्यापारिक माध्यमों से नगद पेमेंट करके हम को ये लेनी चाहिये । आर्थिक सहायता लेना अपने आप को कमजोर बनाना है ।

इस बिल की भावना का मैं समर्थन करता हूं । मैं चाहता हूं कि गुप्त जी इस बिल को वापिस ले लें । दुनियादी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी धन के उपर निश्चित रूप से प्रतिबन्ध लगाना चाहिये ताकि हमारे देश का राजनैतिक और सामाजिक वातावरण पवित्र हो, उसके अन्दर डिगनिटी आए, उसके अन्दर स्वच्छता आए, पवित्रता आए हम और अपने राष्ट्र की अतीत और वर्तमान की जो स्वस्थ परंम्परायें है उनके आधार पर हम अपने राष्ट्र को खड़ा कर सकें ।

17 hrs.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Mr. Chairman, Sir, I am in full agreement with Shri Kanwar Lal Gupta's Bill which has come before the House. I am quite happy that the hon. Minister of Home Affairs, Shri Chavan, has been conscious of the problem long before, and he has been aware of the dangers which may come if the flow of foreign money comes in an invisble manner to individuals and assoociations. After the assurance of the Home Minister I hope that our friends like Shri Gupta how has done a great service by bringing this Bill before the House will help us so that a new Bill can come which can tackle this new danger.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member may come to the front so that he may be audible.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Yes. Sir. I was submitting that I was in full agreement with Shri Gupta's Bill and I was happy that the hon. Minister has been aware of this problem earlier, and he has also assured this house that a fresh Bill can come forward which can safeguard and can save us from the dangers of this inflow of foreign money to individuals and associations and to political parties.

Sir, in this connection, I wish to bring just two or three more points which may be relevant to our debate. If we just read our ancient history also, we find this. In the days of Lord Krishna, India was not very much united as one nation as we are today. Lond Krishna used to to go every year to the different Kingdoms so that he could forge the idea of unity of the whole of India. Once after he returned from the tour of the various kindoms he was questioned by the parliament of those days of the Yadavs, as to the amount of money he had spent in meeting the kings of the different kingdoms. It was some members, those who were in the Opposition, who questioed the wisdom of Lord Krishna's spending this money and going abroad. But then those who were in the Treasury Benches including Lord Krishna defended it and said that this money had been spent to safeguard the way of life, democratic life, that we want to cherish and foster and to help forge the integration of the country. Therefore, thay said, this money was spent. After his explanation, there was overwhelming support both by the opposition and the Treasury Benches- They agreed that this money was spent for good purpose and the aim was quite good.

Today we cannot avoid the tripolar world. It was hitherto a bipolar world, but the world has now been divided into three spheres of influence. Previously, there were only two powers, and now a third power has come in. It is not a new thing. It has happened in history. An attempt will go on when every power will try to build up its own sphere of influence. Here is a very delicate political struggle that we are facing. The struggle will be, on the one side, there will be the capitalist and the feudalist way of life, and on the other, there will be a regimented way of life, and on the third side, when we are fostering the democratic and socialist way of life, there is the danger of our democratic and socialist way of life being in jeopardy, from two parties: one is from those who want to foster regimentation and the other is from those who want to foster feudalism and capitalism. Therefore, today, in our country every man, every Indian, should be very much beware of the great task before us. If we are aware of this great danger and task that we are facing today, in view of the conflict between these three forces, I hope we shall be very much careful about the inflow of foreign money that is coming from all directions to our country.

We shall have to be careful about two things. If anything comes at the governmental level to foster our economy, to strengthen our ways of life and to see that our democracy and socialism gather momentum, that is welcome, and that is the correct approach to the problem. But we shall have to see that it comes at the governmental level. But if anything comes to subvert our way of life, our democracy and our parliamentary institutions which we are builng with pain and labour, that is dangerous and should be stopped. To whichever party money comes, to whichever party the man who receives the money may belong, Government will have to take stern measures about it.

It has been found that since 1967 foreign money is coming in various forms to different political parties, organisations and individuals. I am not sure whether Government has kept a strict watch over it, Sir, sometime back it came to your knowledge and you yourself raised it here. There are vast deposits of foreign funds and sometimes they are withdrawn. What for are they withdrawn and how are they spent? There are universities in this country coming under the control and influence of foreign elements. This is a great—danger. We are seized of this matter in time and we shall not allow it to continue still further Before 1972, we should be in a position where the

[Shri Chintaman Panigrahi]

loopholes are plugged, so that our ways of life, our democratic and political institutions, are not in jeopardy. Government should take not of it. I am sure the Home Minister would take the necessary steps.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, जो विधेयक श्री कंवरलाल गुप्त ने पेश किया है, मैं उसके सिद्धांत की ताईद करता हूं। इस समय हमारे देश में विदेशियों का जो पैसा आ रहा है, उससे न सिर्फ हमारी राजनीति, बल्कि हमारा साहित्यिक और सांस्कृतिक जीवन भी दूषित होता चला जा रहा है।

श्री कमल नयन बजाज : उससे नैतिक पतन भी होता है।

श्री मधु लिमये : नैतिक पतन भी उसी में आ जाता है। लेकिन श्री कमलनयन बजाज को शायद पता नहीं होगा कि उनके भाई के बारे में ही कहा जाता है कि शिव सेना जैसे राष्ट्रद्रोही ...(**व्यवधान**).. मैं उनको याद दिला रहा हूं। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। वह तो एक दूसरे ढंग के आदमी हैं।

श्री रा० डो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : किस ढंग के आदमी हैं ?

श्री मधु लिमये : वह दूसरे ढंग के आदमी हैं। वह कैसा ढंग है, वह मैं नहीं कह रहा हूं।

लेकिन श्री रामकृष्ण बजाज के बारे में यह कहा जाता है कि वह शिव सेना जैसे आंदोलन की मदद करते हैं और उसके लिए ऐसे श्रोतों से पैसा आता है, जिससे देश का हित नहीं हो सकता है। जब यहां दो साल पहले सी० आ० ए० के बारे में बहस हुई थी,...

श्री कमलनयन बजाज : जहां तक श्री रामकृष्ण बजाज के रुपयों से शिव सेना की कोई मदद का सवाल है, उन्होंने कोई रुपये की मदद की यह बात बिल्कुल गलत है। यह साम्यवादी लोगों का प्रचार है और उनके पत्रों द्वारा ये खबरें दी जाती हैं। उसको लोग मानें या उसको करेन्सी दें, यह एक अलग बात है। यह दूसरी बात है कि आदमियों का कई तरह से व्यक्तिगत संबंध हो और वे मिलते-जुलते हों। हम लोग भी सबसे मिलते-जलते है। इन दोनों बातों में बहुत फर्क हैं।

श्री मधु लिमये : साम्यवादी लोगों के द्वारा इस बात को उठाये जाने से पहले ही, सबसे पहले बंबई की एक सभा में मैंने इस बात का जिक्र किया था।

इसलिए मेरी जानकारी तो कम से कम साम्यवादी लोगों से नहीं आई है क्यों कि उमानाथ ने बाद में यह सवाल उठाया है।

श्री कमल नयन बजाज : आपकी जानकारी का आधार क्या है ?

श्री मधु लिमये : वह भी दे दूंगा मैं। मैं तो कहता हूं कि अगर सरकार इस मामले में जांच करने के लिये तैयार हो तो इसके बारे हमारे पास जो जानकारी है वह हम सरकार को या कमीशन को देने को तैयार हैं।

श्री कमल नयन बजाज : सरकार को जांच जरूर करनी चाहिए।

श्री मधु लिमये : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सी. आई. ए. के बारे में न्यूयार्क टाईम्स में लगातार कुछ लेख छपे तो सारी दुनिया दंग रह गई कि जिन संस्थाओं के बारे में कभी यह कह भी नहीं जा सकता था कि विदेशियों से इनका कोई ताल्लुक हो सकता है उन संस्थाओं को भी ऐसी दूसरी संस्थाओं के मार्फत पैसा मिला है जिसका अन्तिम स्रोत सी. आई. ए. है। इस वक्त पी. एल. 480 योजना के तहत हमारे यहां अनाज आता है और पैसा अमेरिका के नाम से यहा जमा होता हैं। एक बहुत बडा हमारी करेंसी का हिस्सा अमेरिकी लोगों के हाथ में हैं और उसका इस्तेमाल वह कैसे करते हैं इसके बारे में यह सरकार भी नियंत्रण नहीं रख सकती है। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिसकी तफसील यह नहीं देख सकते। अब इसमें हमको यह

डर लगता है कि इस पैसे का भी हमारे देश की राजनीति को, हमारे देश की जो संस्कृति हैं, और जो शिक्षा संस्थाएं है, उनको प्रभावित करने के लिए नाजायज ढंग से इस्तेमाल किया जाता होगा। इसकी भी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से अमेरिका और पश्चिम से पैसा आता है, मिशनरी लोगों के द्वारा पैसा आता है, उसी तरह से जो आज रूसी खेमा है उसके द्वारा भी भारत में पैसा आता है। मैं सिर्फ दो उदाहरण दूंगा। सोवियत रूस के द्वारा जितना साहित्य प्रकाशित किया जाता है, अगर मैं केवल राजनैतिक प्रचारात्मक साहित्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, रूसी एजेंसी के द्वारा जैसे टालस्टाय या दोस्तोवस्की की जितनी रचनाएं हैं या और बहुत सारे जो रूसी साहित्यकार हैं उनकी किताबें बहुत सस्ते दर से यहां बेची जाती हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने रुपये की किताब हर साल इस देश में आती है, क्या इनके बिल वगैरह के बारे में इनको कोई जानकारी है और क्या इसका पैसा वापस भेजा जाता है रूस में ? अगर नहीं भेजा जाता है तो उसका साफ मतलब है कि यह व्यापारिक व्यवहार नहीं है। मुफ्त में साहित्य भेजा जाता है, यहां पर वह बेचा जाता है और जो पैसा मिलता है उससे, वह राजनैतिक कामों के लिए यहां खर्च किया जाता है। तो क्या मंत्री महोदय इसके बारे में इस सदन को अवगत कराएंगे कि यह जो रूसी साहित्य का प्रचार इस देश में हो रहा है उसके बारे में व्यापारिक स्थिति क्या है और यह पैसा किन मदों में खर्च होता है ? क्या यह वापस जाता है इसमें से कुछ हिस्सा इसके बारे में सदन को यह जरूर अवगत कराएं।

और एक बात मैंने सुनी है कि रूसी एरिया के तहत पूर्वी यूरोप के देशों को जो माल निर्यात करते हैं उनमें से एक दो व्यापारियों से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे यह कहा कि रूसी प्रतिनिधि मंडल के लोग या दूसरे पूर्वी यूरोप के लोग उनसे सीधा कहते हैं कि दाम क्या है, अगर वह कहते हैं कि सौ रुपये तो वह कहते कि नहीं 110 रुपया दाम रखो और दस रूपया जिन व्यक्तियों को हम कहेंगे उनको दीजिएगा।

श्री कमल नयन बजाज : दस नहीं पांच ।

श्री मधु लिमये : वह दस हो, पांच हो, तीन हो, या एक हो जहां करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो तो एक परसेंट भी कितना हो जायगा ? एक करोड़ पर एक लाख हो जायगा। जब मैंने उनसे कहा कि आपका नाम क्या मैं सरकार को बता दूं, आप सामने आने के लिए तैयार हैं ? तो वह कहते हैं कि दोस्ती में मैंने आपसे कह दिया तो हमारा ही पेट काटने के लिए बात आप कर रहे हो क्योंकि हम निर्यात पर ही निर्भर हैं तो हमारा नाम मत बताइएगा। हम सीधी बात आपसे कह रहे हैं कि ऐसी बातें हो रही हैं। तो मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि चाहे अमेरिका द्वारा हो या रूस के द्वारा हो, या अन्य देशों के द्वारा हो, जो पैसा इस तरह हिन्दुस्तान में आता है और हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन का जो स्त्रोत है उसको दूषित करने का जो प्रयास किया जा रहा है क्या इसके बारे में मंत्री महोदय कुछ कहेंगे ?

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि चौथे आम चुनाव के बाद यहां पर बहस चली और मंत्री महोदय ने कहा कि हम जांच करवाएंगे। सेन्ट्रल ब्यूरो के द्वारा जांच की प्राथमिक रपट भी इनके पास आई लेकिन कभी इस रपट का सारांश इन्होंने इस सदन के सामने नहीं रखा और जिन दलों के बारे में आरोप किया जाता था, जिन संगठनों के बारे में आरोप किया जाता था, उनको अपनी सफाई देने का भी इन्होंने मौका नहीं दिया। नतीजा यह होता है कि आज सारा वातावरण धूमिल होता चला जा रहा है। इसलिए मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि उनके पास जितने तथ्य हैं वह तथ्य ये सदन के सामने रखें। सदन के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाहर रखने के लिए कहेंगे तो हो सकता है कि बदनामी वगैरह के मुकदमे चल सकते हैं। लेकिन सदन में चर्चा के लिए अगर यह सारी जानकारी रखेंगे तो हर

[श्री मधु लिमये]

एक दल के प्रतिनिधि यहां पर हैं, उनको अपनी बात कहने का भी मौका मिलेगा और अंत में मंत्री महोदय को उनकी सफाई का मौका भी मिलेगा। जो विधेयक कंवरलालजी ने पेश किया है उसी तरह के कुछ विधेयक मैंने भी पेश किए हैं और मंत्री महोदय ने वचन दिया था कि जितने निजी सदस्यों के विधेयक हैं उनका अध्ययन कर के सरकार के द्वारा इसके उपर कोई विधेयक प्रस्तावित किया जायगा। तो इस तरह का कोई ठोस आश्वासन मंत्री महोदय देते हैं तो मैं अपने दोस्त से कहूंगा कि मंत्री महोदय के आश्वासन को वह मानें और अपने विधेयक को वापस लें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन उनकी पूर्ति होनी नहीं है। जब मैंने मैनेजिंग एजेंसी और कम्पनी डोनेशन के बारे में विधेयक पेश किया तो आप लोगों ने कैबिनेट में उसके उपर निर्णय किया कि मधु लिमये से कहा जाय कि वह विधेयक वापस लें और सरकार विधेयक लाएगी। मैंने वापस लिया। उसके बाद एक साल तक हर शुक्रवार को यहां खड़े होकर मुझे कहना पड़ता था कि आपका विधेयक कब आएगा। एक साल के बाद आपने विधेयक पास किया। ऐसे ही आपने निजी कोष के बारे में भी हमें आश्वासन दिया। आप ने तो उस दिन बयान दे कर छूटने की कोशिश की कि बजट सत्र में पेश करेंगे, लेकिन जहां तक मुझे पता है आप ने यह आश्वासन दिया था कि बजट पेश करने के पहले यह विधेयक आप लाएंगे। अभी तक आप ने उसे पेश नहीं किया। तो कम से कम विदेशी पैसे के बारे में इस तरह का आश्वासन न हो। जो आश्वासन दे वह सोच समझ कर और ठोस आश्वासन दिया जाय जो कि समय-बद्ध हो और उस का पालन किया जाय।

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA (Anand): Mr. Chairman, Sir, I appreciate the motives of Shri Kanwar Lal Gupta for bringing forward this Bill. The history of India has been very tragic. For centuries we have suffered through foreign cleverness and have been a prey to that. For example, the British company came to India with the very subtle idea of doing business but they took advantage of our internal quarrels and ultimately from a trading company became the emperors of India. So, we should be very careful in dealing with foreign money and how it is spent.

We are a sovereign country. So much money is flowing into this country from various cultural, religious and missionary organisations. I appreciate that the missionaries would like to serve humanity; they have a laudable idea but here in India they have been converting the poorer sections of our countrymen, the Bhils or the Adivasis. Naturally, those people look towards foreign money. They are being educated but they have education of a different type. So, this money which flows into India for laudable purposes ultimately goes against the culture and heritage of India.

The answer to this is that we must have our own money to these backward people and prevent them from becoming a prey to other religious sentiments. We are an open country but, at the same time, openness does not mean that we should be robbed of our own culture and bring foreign elements who will ultimately harm the nation.

So much talk has been going on about foreign money. My hon. friend. Mr. Onkarlal Bohra, very rightly said that money is necessary for the upliftment of our backwardness, as far as technical know-how is concerned and also for our defence needs. But it is shameful that for the last several years we have been importing wheat from foreign countries although the United States may be giving us as a dole. Even the Russians have also offered to supply wheat to us. It is shameful for us, as Indians, that we have to depend upon foreign countries for our very existence. So many times Government have assured us that this import of foodgrains will be stopped. But we have yet to see a day when these imports of foodgrains are completely stopped.

It is a dangerous trend for various organisations to enter into Indian politics, directly or indirectly, through financing cultural activities or financing certain literature from foreign funds. This must be stopped immediately. If the hon. Minister gives

an assurnce, I hope, Mr. Kanwar Lal Gupta will withdraw his Bill and he can depend upon that assarance and there should be a follow-up, as Mr. Madhu Limaye said.

We have to be very careful. Our large-heartedness is responsible for many calamities. Even during the battle of Panipat, we had iuvited foreigners to help against our own brother enemies. That tragic history should not be repeated by our over-enthusiasm in receiving foreign doles. If one party takes foreign money to defeat a particular party, this very party that is defeated will take money from another source and defeat others. We are seeing what is happening right from Vietnam to Middle-East and South-East Asian countries. We should learn from our past history that these foreign countries with laudable means try to help us but, ultimately, we go under them and become their subjects.

This history should not be repeated. This foreign money should be debarred for all the purposes of propaganda. The Asian countries should also be told about it. In Asian meetings, we should be hammering this point to them and we should prevent our brother Asia nations from taking foreign assistance. I, therefore, plead with the Government to take strong measures and prevent foreign money flowing into our country and into our life-blood.

With these words, I would request my hon. friend, Mr. Kanwar Lal Gupta, if an assurance comes from the hon. Home Minister, to withdraw his Bill.

श्री भोलानाथ मास्टर (अलवर) : सभापति महोदय, मैं केवल एक ही विषय पर बोलना चाहता हूं, जिसका जिक्र यहां पर होने से रह गया है । अभी सी०आई० ए० का जिक्र किया गया, रूस का जिक्र किया गया, लेकिन चीन का जिक्र किसी ने नहीं किया । इस संम्बध में मेरा एक प्रश्न था–जिसको केरल की असेम्बली में भी उठाया गया था कि वहां पर बहुत सा लिटेचर और रुपया बुकसेलर्ज की मारफत आता है और उस प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया गया था कि यह बात सही है । यह प्रश्न इस में भी मैंने उठाया था और मेरे प्रश्न के उत्तर में होम मिनिस्ट्री ने यह जवाब दिया कि अभी हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे कि उस रुपये को जो किताबों की शक्ल में या और किसी रूप में जाता है, रोक सकें ।

इस लिये मेरा निवेदन यह है कि जहां रूस और अमरीका के रुपये के बारे में चर्चा हुई है, चीन से जो रुपया आ रहा है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिये । बंगाल में आज जो कुछ दंगे हो रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, वह सब इसी वजह से है–इन सब बातों के लिये चीन का रुपया बंगाल में पहुंच रहा है । मैं इसके सम्बन्ध डाक्यूमेंट्री प्रूफ आपके सामने रख रहा हूं । इस लिये जो कोई भी बिल यहां पर लायें, वह इस तरह का होना चाहिये जिसमें लिट्रेचर वगैरह का जो रुपया आता है, उसको भी रोका जाना चाहिये । इलैक्शन टाइम पर यह चर्चा करना कि फलां पार्टी ने इतना रुपया लिया, उस पर ही रोक लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो रुपया हमारी रोजाना की लाइफ में किताबों और लिट्रेजरकी शक्ल में आता है, उसको भी रोका जाना चाहिये । जो बिल आप यहां पर लायें, वह कंवरलाल गुप्ता जी के बिल से अच्छा होना चाहिये, उसमें इस प्रकार की किताबों वगैरह के बारे में भी कानून होना चाहिये ।

SHRI RAJASEKHARAN (Kanakapura): I must congratulate Mr. Gupta for having brought this Bill before this hon. House. As you are aware, most of the countries in the world today, particularly, the big countries are very much interested to subvert the democracy to which we are holding so fast and so dear. In this power politics, unfortunately, everybody would like to bring his influence either through money or through power or through some political influence. In this situation, the Government has to take certain steps to

[Shri Rajasekharan]

see that such influences would not have any effect either on political Parties or on individuals or on such organizations which are carrying on their activities in this country. Unfortunately, there is no check which is being exercised by the Government on certain organizations and individuals who receive foreign money from time to time. This Bill would enable the Government to take certain effective steps to curb this tendency which is going to have a very bad effect in the ultimate analysis.

As you are aware, we are reading in newspapers also time and again that the money which is being ploughed to this country through various non-official organizations and also through individuals is having a very bad effect not only on the political life of the country but also the social and otherwise. Therefore, I would request the Home Minister to accept the suggestion and bring forward a Bill before this House which would curb such tendencies in future. What is happening today in every country, particularly in underdeveloped countries ? Due to poverty, ignorance and illiteracy many people are subjected to certain pressures either through the pressure we get through finances or the pressure we get through power. We are from time to time subjected to such pressures. If we want to curb this tendency, the only way is to have an effective law at the disposal of the Government and implement it effectively. With these few words, I would request the Government and the Home Minister to bring forward a Bill to curb such tendencies so that our democracy can be safe.

श्री शशि भूषण (खरगोन): सभापति जी, मैं श्री कंवरलाल गुप्त जी को धन्यवाद देता हूं, जो बिल वह हाउस के सामने लाये हैं, वह बहुत अच्छे मौके पर लाये हैं ।

सभापति महोदय, आज विदेशों का रुपया जिस तरह से खर्च होता है, उस पहलू पर मैं आपकी मारफत थोडा सा प्रकाश डालना चाहता हूं । पान-इस्लामिक मुवमेंट भी सी०आई०ए० के पैसे से चलता है । जो अरब दुनिया के राजे-महाराजे बड़े बड़े फ्यूडलिस्ट्स हैं, उस रुपये से उनको सी० आई० ए० मजबूत करते हैं और वहां की जनता की ताकतों को कमजोर करते हैं । सी० आई० ए० ने हमारे देश में भी पिछले दिनों धार्मिक भावनाओं को भड़काने में काफी दिलचस्पी ली है । मिसाल के तौर पर हमारे पब्लिक सैक्टर में, जिनको हम अपनी जनता के मन्दिर कहते हैं, जितने भी फिसाद हुए, वे इसीलिये कराये गये ताकि वे पब्लिक सैक्टर फेल नाकामयाब हो और इसमें सी०आई० ए० का पैसा लगता है ।

पिछले दिनों जब यहां पता लगा कि सी० आई०ए० एशिया फाउन्डेशन के जरिये कितने लोगों को फाइनेन्स करता है तो मालूम हुआ कि उसमें इस देश के बड़े बड़े महान नेता और बहुत सी संस्थायें भी शामिल थीं । जिन्होंने बाद में उन संस्थाओं से इस्तीफा दिया और कुछ नेताओं ने वह पैसे भी वापिस किए । मैं कहना चाहता हूं कि सी०आई०ए० का कोई रिटेन कांस्टीट्यूशन नहीं है । इसी प्रकार से इस देश में धार्मिक आधार पर युवक संस्थायें काम करती हैं जिनका कोई रिटेन कांस्टीट्यूशन नहीं है । गुरु दक्षिणा के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं और सी०आई०ए० से ताल मेल रखते हैं और देश के पब्लिक सैक्टर को तथा देश की तरक्की को रोकने की हरचन्द कोशिश करते हैं । इस बात से मैं सदन को आगाह करना चाहता हूं । खास तौर से हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे अखबार हैं जोकि हिन्दुस्तान की सांस्कृतिक और धार्मिक कमजोरियों का फायदा उठाकर सी०आई०ए० के हाथों में खेलते हैं । सी०आई० ए० की तरफ से जो पैसा मिलता है, हम चाहते हैं कि उसकी जांच हो । लीबिया अफ्रीका में एक छोटा सा देश है । वहां पर डालर उसकी करेंन्सी है और जो रबर पैदा होती है उसका लाभ सिर्फ फायरस्टोन कम्पनी वाले उठाते हैं । प्रेसीडेन्ट का बंगला भी इस कम्पनी ने बनाया है । किसी जमाने में वहां से चावल एक्सपोर्ट किया जाता था लेकिन आज बाहर से वहां प्याज तक भी इम्पोर्ट होता है । इस प्रकार से सारे देश को एक विदेशी

कम्पनी सी०आई०ए०की सहायता ने प्याज तक भी खरीद रखा है। हमारे देश में भी एस्सो पेट्रोल लाबी, फायरस्टोन लाबी जैसी विदेशी कम्पनियां हैं जो कि काफी पैसा बहाती हैं। देश के बडे सर्मायेदारों के पास पैट्रोल के नाम पर और दूसरे नाम पर सी०आई०ए० का पैसा आता है और उससे इस देश में प्रजातंत्र का जो तरीका है उसको धक्का पहुंचाने की कोशिश की जाती है।

आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्टों से हमारा विरोध है लेकिन कम्युनिस्टों को हम अपने प्रजातांत्रिक तरीके से, अपने सिद्धांत से परास्त कर सकते हैं। सी० आई०ए० से पैसा लेकर कम्युनिस्टों को खत्म करने से पहले हमें चीन के च्यांगकाईशेक से सबक लेना चाहिए। इसी प्रकार से अगर कम्युनिस्ट चाहें कि किसी देश से पैसा लेकर हिन्दुस्तान के प्रजातांत्रिक ढांचे को खत्म किया जाये तो वह भी सम्भव नहीं है। वह स्वंय भी चुनकर आ सकते है। ऐसी नीति भी दूसरे देशों में फेल हो चुकी हैं। हमारा जो प्रजातांत्रिक तरीका है वह अपने आप में समर्थ है। हम जिस प्रकार से आगे बढ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हम आगे तरक्की करते जायेंगे।

जो लोग इस प्रकार से पैसा लेकर इस देश की राजनीति को गन्दा करते हैं, सुबह से शाम तक छोटे छोटे बच्चे युवक लाठी चलाते हैं, इस प्रकार के जो संघठन हैं जैसे आर. एस. एस. उसके पास 60 करोड़ रुपया है.... (**व्यवधान**)...सी. आई. ए. से ताल मेल रखते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि आर० एस०एस० का आप कांस्टीट्यूशन बनाइये, विधान बनाइये। इस प्रकार का जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है—चाहे रूस से आता हो या अमरीका से आता हो उसको रोकना होगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि पास के देश नेपाल तक से यहां पर पैसा आता है। नेपाल के चार पांच व्यापारी करोडों रुपए का फायदा हमारे देश से उठाते हैं। जब कभी कोई आर्थिक आंच उनपर आती है तो सारे नेपाल में आन्दोलन खड़ा हो जाता है। हिन्दुस्तान में नेपाली व्यापारियों के एजेन्ट मोजूद हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे देशों जैसे इजराइल तक से रुपया आता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस देश में प्रजातन्त्र काफी मजबूत है और हमारे संसद सदस्य सजग हैं। गुप्ता जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि वे इस बिल पर वोटिंग न करायें। हमारे गृह मंत्री महोदय अपने आप कोई सही रास्ता निकालेंगे। इतना कह कर मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, मुझे यह तो अनुमान था कि श्री शशि भूषण के सम्मुख प्राय: सत्य का कोई मूल्य नहीं रहता, वे दूसरों पर अनाप शनाप आरोप ही लगाना जानते हैं ...(**व्यवधान**)

श्री शशि भूषण : मैं ने तो इनका नाम भी नहीं लिया। ये आर०एस०एस० के मेम्बर हैं.....(**व्यवधान**)

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं इसमें कोई संकोच नहीं करता। मैं आर०एस०एस० का वर्कर हूं और इसपर मुझे अभिमान है। मैं चाहूंगा कि शशि भूषण जी की सलाह मानकर चव्हाण साहब निश्चित रूप से इस बात की जांच करवाये कि क्या सन 25 से लेकर आजतक जबसे कि आर०एस०एस० का जन्म हुआ है कभी भी विदेशों से एक पैसे से भी संबंध रहा है और अगर यह साबित हो तो मैं लोकसभा से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा -अगर वे अपनी कोशिशों के बाद यह साबित कर सकें कि आर०एस०एस की एक कौडी भी बाहर से आई है। आर०एस०एस० की भावना को प्राप्त करने या उसको समझाने का काम शशि भूषण

[श्री श्रीचन्द गोयल]

जी कई जन्म के अन्दर भी नहीं कर पायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आर. एस. एस. के हजारों लोग बहादुर लोग हैं। कोई शिविर हो या कोई कार्यक्रम हो उसमें बिल्कुल गरीब से गरीब परिवारों से सम्बन्ध रखने वाले बच्चे एक एक पैसा रोज बचाकर साल में दक्षिणा देते हैं।....(**व्यवधान**) आप सुन लीजिए जरा, आरोप लगाना सरल होता हैं लेकिन मैंने तो चुनौती दी है।

सभापति महोदय : शशि भूषण जी, जैसे आपकी बात शांतिपूर्वक सुनी गई उसी प्रकार आप भी सुनिये।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि चव्हाण साहब निश्चित रूप से इसकी जांच पडताल करवायें क्योंकि आरोप लगाना सरल होता हैं उसमें किसी का कुछ बिगड़ता नहीं। आखिर मैंने भी आर०एस० एस० के एक प्रचारक के तौर पर दस साल तक सारे प्रान्त का प्रमुख रहकर काम किया है और इसलिए मुझे पता है कि आर. एस. एस. में लोगों को किस प्रकार देश के लिए बलिदान होना, कैसे त्याग और कुर्बानी करना, कैसे अपने परिवार की कमाई में से एक एक पैसा जोड़कर अपने कार्यक्रम के लिए चन्दा देना, यह सब सिखाया जाता है। मेरे साथी जो अभी बोल रहे थे वैसे तो मेरे मित्र हैं, इनके साथ मेरी काफी घनिष्टता है लेकिन जिस प्रकार से वह अनाप-शनाप आरोप लगाते है..(**व्यवधान**) और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की है.. (**व्यवधान**)... मैं समझता हूं यह इस समय का विषय नहीं है, हम विषय से थोड़ी दुर जा रहे हैं।

आज जिस आशय का विधेयक गुप्त जी ने इस सदन के सामने पेश किया है उसको मैं समझता हूं। इस सदन के सभी सदस्यों ने अपना समर्थन दिया है और मैं समझता हूं कि इस देश में जनतन्त्र के स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए इस बात की बड़ी आवश्यक्ता है। खास तौर पर गृह मंत्री जी ने इस सदन में जो वक्तव्य दिया था वह मुझे याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ सूत्रों से इस प्रकार की भी जानकारी उनके पास आई है कि सन 1967 के चुनाव के अन्दर विदेशी पैसे का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन उसकी जांच वे आजतक नहीं करवा पाये। मैं समझता हूं कि अगर उसकी भी जांच करवाई जाये तो इसके अन्दर कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश की राजनीति विदेशी पैसे की सहायता से चले, हम अपने चुनावों को चलाने के लिए विदेशों से छिपे तरीके से धन लेकर उसका इस्तेमाल करें इससे हमारे देश का स्वाभिमान नष्ट होता है, देश की स्वतंत्रता दुर्बल पड़ती है। मैं समझता हूं कि आज दुनिया के अन्दर जो दूसरे देश हैं वे अगर इस ढंग से पैसे की सहायता हमारे देश में करेंगे तो अपने सामने कोई उद्देश्य रख कर, अपना मकसद पूरा करने के लिए ही करेंगे। केवल पिछड़े हुए देश की सहायता करने की भावना से मैं समझता हूं कम ही देश होंगे जोकि सहायता करेंगे। इसलिए कम में कम मैं तो इस विचार धारा से ताल्लुक रखता हूं कि हमको न एक कौड़ी अमरीका से चाहिए न एक कौड़ी रूस से चाहिए और न एक कौड़ी चाइना से चाहिए। हम कुर्बानी करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे और जिन्दगी की दूसरी जरूरतों को कम करके भूखों मरना पसन्द करेंगे लेकिन विदेशों के पैसे पर हमारी राजनीति बने, इससे मुझे तो कम से कम सख्त नफरत है और हमारे दल को नफरत है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जब इस आशय का विधेयक इस सदन के अन्दर आया है कि जो पैसा विदेशों के जरिए आता है उसका हिसाब-किताब रखने में क्या आपत्ति है? आपको स्मरण होगा कि कुछ दिन पहले इस सदन के अन्दर मेरे एक प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर इस प्रकार का बंधन लागू किया जाये कि वे अपना पूरा हिसाब किताब रखें और उसकी आडिटिंग भी होनी चाहिए ताकि सारे देश को इस बात की जानकारी हो सके कि आखिर ये जो दल हैं वे किस प्रकार के धन से चलते हैं। और

जहां तक विदेशी धन का प्रश्न है उसका तो निश्चित रूप से हर हालत में हिसाब किताब रखा जाना चाहिए । ताकि वह चीज किसी से भी छिपी न रह सके । मुझे पता है कि अनेकों देश इस देश में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिये अनेकों तरीके से अपना धन खुले तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं । कोई किसी तरीके से कर रहे हैं, कोई किसी तरीके से कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : कल्चरल आर्गेनाइजेशन्स ।

श्री श्रीचन्द गोयल : कल्चरल सोसायटी के नाम पर शायद वे लाखों रुपये हड़प कर जाते होंगे । उनको शायद इसके अन्दर कोई संकोच नहीं है । लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि किसी रूप से आये, किसी माध्यम से आये और किसी साधन से आये, विदेशी लोग अपना धन इस देश में बड़े सरमाये के रूप में लगा कर के निश्चित रूप से यहां पर अपना प्रभाव कायम करना चाहते हैं । वह प्रभाव हम लोगों की अपनी स्वतन्त्रता की भावना को कम करता है ।

आखिर दूसरों के सहारे हम कब तक जिन्दा रहेंगे । हमें उदाहरण लेना चाहिये दूसरे देशों में खास तौर से मैं चीन की तारीफ करूंगा इस दृष्टि से कि उन्होंने विदेशों से सहायता लिये बगैर अपने देश का विकास किया है और सब प्रकार का विकास किया है । आज हम क्यों अपने देश में तय नहीं कर सकते कि हम अपने देश का विकास आत्म-निर्भर हो कर करेंगे, अपने बल बूते पर करेंगे ? आज जो धन गलत तरीके से और गलत कामों से चोरी छिपा करके आता है, उसका तो निश्चित रूप से हिसाब किताब रक्खा जाना चाहिये। और इस विधेयक के अन्दर यही मासूम सी मांग की गई है । मेरी समझ में नहीं आता कि इसके ऊपर सरकार को क्यों आपत्ति होनी चाहिये । आज क्यों यहां लोगों की ओर से यह बात कही जा रही है कि श्री गुप्त अपने इस विधेयक को वापस ले लें । आखिर यह एक अच्छी चीज है । यह विरोधी दल से आई हो या किसी और दल से आई हो, इसका स्वागत करना चाहिये । हम इसकी भावना के साथ चलें । इससे देश की बहुत भारी सेवा होने वाली है । हमारे देश की राजनीति विदेशी प्रभावित न कर पाये, विदेशी लोग इस को दूषित न कर पायें, भ्रष्ट न कर पायें, इसके लिए कुछ नियम बनाना, कुछ उसूल तय करना, कुछ हिसाब किताब की परिपाटी डालना, बहुत आवश्यक है । जिस प्रकार से आज श्री गुप्त के बिल का सारे सदन ताव्वुन दिया हैं, पूरी तौर पर इसका समर्थन किया है, उसे देखते हुए मैं अपने गृह मंत्री से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वह इस बिल को भी स्वीकार कर लें और जो भी जानकारी उनके पास इस प्रकार की है कि पिछले चुनाव में विदेशी धन का उपयोग हुआ है, उसकी भी जांच करायें । मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा कि खास तौर से हमारे आर० एस० एस० के बारे में सब से पहले जांच पड़ताल करें ताकि जो आरोप रोजाना यहां लगाये जाते हैं श्री शशि भूषण या दूसरों के द्वारा उनको निरस्त किया जा सके ।....

(**व्यवधान**) .....

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : Earlier we had requested the Government to make a statement, on the Kashmir issue. May we suggest that the Home Minister make a statement before we adjourn because this is important?

MR. CHAIRMAN : The request has been conveyed to them. They will make a statement at their convenience.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Is he making a statement at all?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I am willing to make a statement, but I can only make it on the basis of the information that I have got. I am prepared to make a statement even this minute.

MR. CHAIRMAN : Let this be over.

SHRI A. SREEDHARAN (Badagara) : I wellcome this Bill, but still I feel that when we consider the magnitude of this problem, when we take into account the great threat that is hanging over our country in the form of foreign money and its influence, Shri Gupta's Bill does not even touch the fringe of the problem.

After the Second World War, the old colonialism which had fallen took a new shape and the new colonial Powers changed thier tactics and used new methods to influence the nations of Africa and Asia.

This is not a problem peculiar to India alone. In very under developed country the two power blocs are exercising their influence and control them through financial enfluences. This has been happening in India also. The blame for not defeating it lies squarely on the shoulder of the Home Department of the Government of India. Sometime back this House discussed the issue about Chinese money reaching some citizens in Kerala and Mr. Namboodiripad the then Chief Minister of Kerala himself stated in the Kerala Assembly that the Chinese money was sent by postal money order to some persons in Kerala but the Government of India slept over this and did not take further steps or action against those persons who were receiving foreign money from embassies in this country. It also came to light that those persons who receives Chinese money and formed themselves into a group started violence in the State and attacked police stations. The very persons who received Chinese money led the Naxalite attack on the police station in Pulapalli. If the Government had taken power or enforced the power that it already had in its hand, this situation would not have arisen.

Another instance came to our notice. The Soviet Cultural Centre in Trivandrum collapsed. The patriotic soil of Kerala refused to hold it and from the accounts of the money spent by the Sovlet Embassy it came to light that Rs. 45,000 was paid to the President of the United Congress for handing over thai building and the site to the Russian Embassy....(*Interruptions*). The United Congress? The Congress before the split, when you were hand in glove with each other. This building and the compound were owned by another person and the Kerala Pradesh Congress Committee was only renting that building. But when this building was taken over by the Russian Embassy Rs. 45,000 was paid to President of the Congress for the so-called improvements mode. Later on it came to light that not only did the Russian take advantage of the improvements but they also demolished the improved building. It is thus clear that with the connivance of this Government and the clearance of this Government, right under the nose and eyes of this Government, foreign money had played a very nasty role in the development of our political system and the poltical parties has been going about spending lakhs of rupees in elections. This danger has not been fought out by the Government.

American money is flowing into India. There is no doubt about it. CIA money comes to India in every election. There is CIA money on the one hand and Russian money on the other. We are told that the Chinese are now distributing counterfeit currency on Indian borders. This way, every attempt is made to destroy the integrity and democratic system in this country. So, this problem needs drastic solution. It is a dangerous disease which needs a drastic remedy. Guptaji's bill does not go that far. My suggestion is that instead of looking into the accounts or ordering an audit, if any private agency is to be helped by any other country, it should in the first place ask for assistance only through the Government of India. If any private agency has to receive money, that should be done. There are a number of missionary institutions in Kerala which receive money. There were complaints on the floor of the Kerala Assembly that some of the leaders of the Congress Party were receiving money and they were running a press with foreign help. These printing press was utilised in the elections. They were publishing a paper; he is the leader of the Syndicate Congress in the Kerala Assembly. So, this complaint has come, and I know that the Central Intelligence has reported this long back to the Home Minister. Even photostat copies of the cheques received by this Congress leader were passed on to the Home Minister. No action has been taken.

Like this, foreign government are sending money. Therefore, it must be made clear when the Government brings a Bill-I hope the Government will come out with a Bill-and when they enforce the law, it must be made categorically clear that no citizen of India, no private agency in India, should receive money from foreign institutions, foreign agencies and foreign power except through the Government of India. If such a stringent measure could be brought out, then alone can this problem be confronted. I hope the Government will accept this Bill and welcome it, instead of standing on prestige, and adopt this Bill. I hope they will amend it in such a way as to make the law plug all the loopholes and save our democratic system from foreign influence which is the biggest danger that we are facing today.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड) : मैं श्री कंवरलाल गुप्तजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को उपस्थित कर देश के ऐसे जलते हुए प्रश्न को छुवा है जो भारत के हर स्वाभिमानी मस्तिष्क को चिन्तित बनाए हुए था।

इसमें ज्यादा चर्चा जो बाहर से पैसा आता है, उसकी हुई है। अमरीका से पैसा आ रहा है, रूस से आ रहा है, चीन से आ रहा है, उसकी ही हुई है। लेकिन एक और देश भी है जो भारत का पड़ौसी है और जिसने भारत के साथ शत्रुता के मामले में एक मुकाबला कर रखा है दूसरे देश से। उसका नाम है पाकिस्तान। उसकी ओर भी मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान जाए। विदेशों से जो गलत रास्तों से पैसा आता है, उसमें केवल तीन देश नही हैं बल्कि हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान भी है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

राजनैतिक दलों को जो रुपया आता है, उसके सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि हमारे पास गुप्तचर विभाग की इस प्रकार की रिपोर्ट है जिससे पता लगता है कि बाहर से कुछ पैसा आया है। लेकिन उस समय गृह मंत्री जी इस बात का संकेत नहीं दे सके कि वे कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जो इस प्रकार से अवैध रूप से बाहर से पैसा लेकर हिन्दुस्तान में अपनी राजनीति चलाते हैं। प्रत्यक्ष न सही, अगर किसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप में भी उनके द्वारा कुछ संकेत इसके बारे में मिल जाए तो मैं समझता हूं कि देशवासियों को अपना मस्तिष्क बनाने में इससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। चोरों का मुंह तो काला गवर्नमेंट को करना ही चाहिये। वे पापी जो इस तरह से बाहर के देशों से पैसा लेकर अपनी राजनीति चला रहे हैं, उस सम्बन्ध में अगर गुप्तचर विभाग की कुछ स्पष्ट रिपोर्ट आपके पास नहीं है केवल संकेत मात्र ही है, तो यह संकेत भी अगर आप किसी प्रकार दे सकें तो मैं समझता हूं कि देश की बहुत बड़ी सेवा आप करेंगे।

पीछे जो पश्चिम बंगाल में मध्यवर्ती निर्वाचन हुए थे उस समय मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री के पास कोई इस प्रकार की रिपोर्ट भी आई थी गुप्तचर विभाग के द्वारा कि कुछ जाली नोट उन दिनों में पश्चिमी बंगाल के अन्दर मिले जो भारत के रिजर्व बैंक के बने हुए नोटों जैसे ही थे। इसका कारण यह है कि वित्त मंत्रालय ने इसकी पुष्टी की थी कि उन्हीं दिनों में इस प्रकार के जाली नोट बड़ी संख्या में मिले थे। आपके गुप्तचर विभाग ने भी क्या उस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट आपको दी? इसका भी आप संकेत दे सकें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा।

श्री श्रीधरन ने एक बात की ओर संकेत किया है। पिछले दिनों गृह मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया था कि विदेशों से जो अवैध रूप से पैसा राजनीति चलाने के लिए भारत में आता है, उसमें राजनीतिक दलों के अतिरिक्त कुछ धार्मिक संस्थायें भी इस प्रकार की है जो धर्म प्रचार के नाम पर बाहर से पैसा ला लेती है लेकिन उस पैसे का तो राजनीति कार्यों में उपयोग करती हैं। मिशनरी एक्टिविटीज विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही है। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां वहां चिन्ता का कारण हो रही

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हैं। ये लोग धर्म प्रचार के नाम पर बाहर से पैसा मंगाते है और हिन्दुस्तान की राजनीति में उसका उपयोग करते हैं। क्यों नहीं इनके ऊपर भी सख्ती से प्रतिबन्ध लगाया जाता है? इस पैसे की सरकार के पास रिपोर्ट आनी चाहिये। यह पैसा धर्म प्रचार के कार्य में लगाया गया है या राजनीति में लगा है, इसकी वार्षिक रिपोर्ट भी सरकार के पास आनी चाहिये और सरकार का इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट होना भी बहुत आवश्यक है।

एक और तरीके से पैसा आ रहा है जिसका राजनीति में उपयोग किया जा रहा है वह पैसा समाचार पत्रों को विज्ञापन आदि के माध्यम से दिया जा रहा है। बाहर से कुछ पुस्तकें आदि भी सस्ते मूल्य पर यहां आकर बिकती हैं। ऐसी ऐसी पुस्तकें बिकती हैं जिनकी अगर रद्दी बेची जाए तो उस रद्दी का मूल्य अधिक होगा बजाय इसके कि जो पुस्तक का मूल्य लिखा रहता है। उसको भारी मात्रा में विज्ञापनों का पैसा दिया जाता है, जिनको देना उनके लिए अभिष्ट होता है। कुछ दिन हुए एक दैनिक समाचारपत्र के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। वित्त मंत्री ने यह बताया था कि नेपाल से इतने हजार रुपया उनको मिला, अमुक देश से इतना मिला। भारत के समाचार पत्रों पर कोई अंकुश इस बारे में अवश्य लगना चाहिये। समाचारपत्र तो प्रकाशित हों लेकिन विदेशी धन के सहारे न हों अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके मन में कुछ न कुछ साफ्ट कार्नेर जरूर रहेगा ही। इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिये।

विदेशी धन जो राजनीतिक कार्यों में प्रयोग होता है उसमें कुछ व्यापारिक संगठनों को भी आता है। इसके जो बीजक बनते हैं उनमें किस प्रकार से झूठे बीजक बनाए जाते हैं और वह पैसा बचा कर राजनीतिक संगठनों को दिया जाता है। इस दिशा में भी कुछ किया जाना चाहिये।

एक और नई प्रवृत्ति अभि प्रारंभ हुई है। देश के अन्दर कुछ राजनीतिक लोगों ने मैत्री संघ बना लिये हैं और उनके माध्यम से भी कुछ सहयोग के नाम पर बाहर से पैसा आता है। भारत अरब मैत्री संघ है। भारत फ्रेंच मैत्री संघ है, भारत नेपाल मैत्री संघ है, भारत श्रीलंका मैत्री संघ है। ये मैत्री संघ कहीं दूसरे देशों से मिलकर अमैत्री का वातावरण तो नहीं पैदा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस पर भी ध्यान दें। मैत्री संघों को जो सहयोग मिलता है उसका भी कहीं हमारे देश की राजनीति में तो उपयोग नहीं किया जा रहा है।

मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय निर्णय लेते समय और सदन को सन्तुष्ट करते समय इन जलते हुए प्रश्नों की ओर भी ध्यान दें सकेंगे तो देश की बहुत बड़ी सेवा हो सकेगी।

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : मुझे होम मिनिस्टर साहब से बड़ी मुहब्बत है। यह बात अलग है कि वह कहीं बैठे हैं और मैं कहीं बैठा हूं। लेकिन मुहब्बत तो नहीं जाती है।

[شری عبدالغنی ڈار (گڑگانو) مجھے
ہوم منسٹر صاحب سے بڑی محبت ہے -
یہ بات الگ ہے کہ وہ کہیں بیٹھے ہیں
اور میں کہیں بیٹھا ہوں-لیکن محبت
تو نہیں جاتی ہے -]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सुना दीजिये न वह शेर जो आप अकसर कहते हैं:—इसमें उलफत जिस तरह होगा निभायेंगे जरूर। तुम हमें चाहो न चाहो, हम तो चाहेंगे जरूर।

श्री अब्दुल गनी डार : होम मिनिस्टर ने हाउस को यकीन दिलाया था कि यह तो मेरे इल्म में है कि रुपया आता है, जो रुपया आता है वह कैसे आता है, किस किस को आता है, भेजने वाले का मुंह काला है या सफेद, उनका कहना था कि यह सब मुझे मालूम है। उन्होंने कहा था कि डिटेल्ज मैं अभी टेबल पर नहीं रखूंगा। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि देश को बचाने के लिए वह कंवरलालजी का सहारा ले लें। कंवरलालजी ने हिम्मत दिखाई है इस तरह के बिल को लाकर। कंवरलालजी की सहायता में गोयलजी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि हमें सब से पहले कसौटी पर कसा जाए और बताया जाए कि हमारे आर.एस.एस. को रुपया मिला है या नहीं। मेरा ख्याल है कि होम मिनिस्टर साहब को मौका मिल गया है कि वह किसी तरह इसकी परख करें।

एक बात पक्की है। 1907 से 1919 तक बाबा ज्वाला सिंह, बाबा गुरदित सिंह, कामा-गाटा मारू जहाज वाले, शहीद-ए-आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजित सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, राजा महेन्द्र प्रताप, जे जे सिंह, जैसे लोगों ने हमको बाहर से रुपया भिजवाया। लेकिन वह पैसा इस वास्ते भिजवाया गया कि मुल्क की आजादी की तहरीक को तकवियत मिले। एक रुपया वह था और एक रुपया वह है जो हमें गुलाम बनाने के लिए आता है। आप मानेंगे कि इस वक्त अमरीका को जलील करने में अपनी तरफ से किसी भी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वियतनाम में उसके सिपाही लड़ रहे हैं, रुपया वह दे रहा है, जुल्म अमरीकी कर रहे हैं, यह सब ठीक हो सकता है लेकिन आप यह भी मानेंगे कि हंगरी में रूस द्वारा की गई कार्यवाही को हम कंडैम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? रुपये का असर था या किसी और का, मैं नहीं जानता। होम मिनिस्टर साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट तो यह है कि वह श्री गुप्त की बात को मान लें।

18 hrs.

मैंने दो महीने पहले, पिछले सेशन में, अर्ज किया था कि अब्दुल्ला गया, बख्शी गया और सादिक की बारी आ रही है। सादिक को गिराने के लिए डी० पी० धर मास्को से आया हुआ रुपया बांट रहा है। शास्त्री जी ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ भी देखो। मैं भी यही चाहता हूं क्योंकि उसकी पर-कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है; वह किसको रुपया देता है, उसका रुपया कहां आता है, यह भी देखना चाहिए। शास्त्री जी ने यह भी कहा है कि भिन्नता के नाम पर कुछ सोसायटियां बनी हुई हैं। उनको भी देखना चाहिए। इस पर भी नजर रखनी चाहिए कि किस किस सफीर के जरिये कितना रुपया आता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि रुपया बाहर से ही आये। इजरायल का कान्सुलेट यहां बैठा हुआ है। कांग्रेस वालों ने मुसलमानों की हमदर्दी में बड़े जोरों से अल-अक्सा के सवाल पर एक जलूस निकाला। उसके बाद इजरायल के कान्सुलेट ने रुपया बांटा। शिव सेना को दिया या किसी और को दिया। लेकिन अहमदाबाद, औरंगाबाद और दूसरी जगहों में फसादात कराए गये।

मेरी अर्ज यह है कि अगर सादिक को भी मारना है, तो शान से मारिये, प्यार से मारिये, मीठा जहर दे कर मारिये। मैंने पंडित जवा-हरलाल नेहरू को कहा था कि आप कामनवैल्थ में शामिल हो रहे हैं, चूंकि हमको आप से प्यार है, इसलिए हम आपके हाथ से इस जहर के प्याले को भी शौक से पी रहे हैं। सादिक को भी अगर जहर का प्याला पिलाना है, तो मुहब्बत से बुला कर पिलाइये, बजाये इसके कि उसको जलील कर के, रुपया बांट कर, सिटुएशन को खराब किया जाये।

شری عبدالغنی ڈار – ہوم منسٹر نے ہاؤس کو یقین دلایا تھا کہ یہ تو میرے علم میں ہے کہ روپیہ آتا ہے – روپیہ آتا ہے وہ کیسے آتا ہے – کس کس کو آتا ہے – بھیجنے والے کا منہہ کالا ہے یا سفید – اُن کا کہنا تھا کہ یہ سب مجھے معلوم ہے – اِنہوں نے کہا تھا کہ دتہلت میں ابھی ہاؤس کی ٹیبل پر نہیں رکھوں گا– میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دیش کو بچانے کے لئے وہ کلورلال جی کا سہارا لیں – کلورلال جی نے ہمت دکھائی ہے اِس طرح کے بل کو لاکر – کلورلال جی کی سہایتا میں گوئل جی بولے ہیں – اِنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کسوٹی پر کسا جائے – اور بتایا جائے کہ ہمارے آر-ایس-ایس کو روپیہ ملا ہے یا نہیں – میرا خیال ہے کہ ہوم منسٹر صاحب کو موقعہ مل گیا ہے کہ وہ کسی طرح اُسکی پرکھ کریں –

[श्री अब्दुल गनी डार]

ایک بات پکی ہے - ۱۹۰۷ سے ۱۹۱۹ تک بابا جھالا سنگھ - بابا گردت سنگھ - کاماگھاٹا مارو جہاز والے - شہید اعظم بھگت سنگھ کے چاچا سردار اجیت سنگھ - صوفی امبا پرساد - راجہ مہیندر پرتاپ - جے - جے - سنگھ جیسے لوگوں نے ہم کو باہر سے روپیہ بھجایا - لیکن وہ پیسہ اِس واسطے بھجوایا گیا کہ ملک کی آزادی کی تحریک کو تقویت ملے - ایک روپیہ وہ تھا اور ایک روپیہ وہ ہے جو ہمیں فلم بنانے کے لئے آتا ہے - آپ مانیں گے کہ اُس وقت امریکہ کو ذلیل کرنے میں اپنی طرف سے کسی بھی پارٹی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے - ویتنام میں اُسکے سپاہی لڑ رہے ہیں - روپیہ وہ دے رہا ہے - ظلم امریکی کر رہے ہیں - یہ سب ٹھیک ہو سکتاہے لیکن آپ یہ بھی مانیں گے کہ ہنگری میں روس دوارا کی گئی کاروائی کو ہم کنڈیم نہیں کر پائے - کیوں نہیں کر پائے - روپیہ کا اثر تھا یا کسی اور کا - میں نہیں جانتا !

ہوم منسٹر صاحب سے میری ایک ریکویسٹ تو یہ ہے کہ وہ شری گپت کی بات کو مان لیں -

میں نے دو مہینے پہلے - پچھلے سیشن میں عرض کیا تھا کہ مہدانند گیا - بخشی گیا اور صادق کی باری آ رہی ہے - صادق کو گرانے کے لئے ڈی - پی - دھر ماسکو سے لیا ہوا روپیہ بانٹ رہا ہے - شاستری جی نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف بھی دیکھو - میں بھی یہی چاہتا ہوں - کیونکہ اسکی پر کیپیٹا انکم ہم سے زیادہ ہے - وہ کسکو روپیہ دیتا ہے - اسکا روپیہ کہاں آتا ہے - یہ بھی دیکھنا چاہئے - شاستری جی نے یہ بھی کہا ہے کہ مترتا کے نام پر کچھ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں - انکو بھی دیکھنا چاہئے - اس پر بھی نظر رکھنی چاہئے کہ کس کس سفیر کے ذریعہ کتنا روپیہ آتا ہے - کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ روپیہ باہر سے ہی آئے - اسرائل کا کانسولیٹ یہاں بیٹھا ہوا ہے - کانگریس والوں نے مسلمانوں کی ہمدردی میں بڑے زوروں سے المکسہ کے سوال پر ایک جلوس نکالا - اس کے بعد اسرائل کے کانسولیٹ نے روپیہ بانٹا - شو سینا کو دیا یا کسی اور کو دیا - لیکن احمدآباد - اورنگ‌آباد اور دوسری جگہوں میں فسادات کرائے گئے -

میری عرض یہ ہے کہ اگر صادق کو بھی مارنا ہے - تو شان سے ماریئے - پیار سے ماریئے - میٹھا زہر دیکر ماریئے - میں نے پنڈت جواہرلال نہرو کو کہا تھا کہ آپ کامنویلتھ میں شامل ہو رہے ہیں - چونکہ ہمکو آپ سے پیار ہے - اس لئے ہم آپ کے ہاتھ سے اس زہر کے پیالے کو بھی شوق سے پی رہے ہیں - صادق کو بھی اگر زہر کا پیالہ پلانا ہے - تو محبت سے پلا کر پلائیے - بجائے اس کے کہ اسکو ذلیل کرکے - روپیہ بانٹکر - سٹوایشن کو خراب کیا جائے -]

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y.B. CHAVAN) : Mr. Chairman, Sir, I am very grateful to Shri Kanwar Lal Gupta for giving an opportunity to this House to discuss this very important question of the foreign money and its role in our political, economic and cultural life. I may remind the House that immediately after the general elections of 1967 we discussed this matter in the House and then I had assured the House that an inquiry, a short of investigation, would be undertaken by the Intelligence Bureau into whatever information that will be possible for us to lay our hands on. I had made a statement on the floor of the House about the broad conclusions that were reached at the end of this inquiry. I had then pleaded with the House, which I would like to do again if necessary, that the character of the investigation was such that it was very difficult to come to any precise conclusions about the nature of assistance, the quantum of assistance or the individuals, organisations or parties involved. I had then broadly indicated the conclusions that were reached and, if necessary, I can indicate them again for the benefit of this hon. House, because I remember I made a statement on the floor of the House.

SHRI RAJASEKHARAN : Why do you not place on the Table of the House a copy of the report and your conclusions ?

SHRI Y.B. CHAVAN : I had explained that it is difficult to lay a copy of the report on the Table of the House. But I had made a statement about it which was laid on the Table of the House and I am making reference to that very statement. Broadly, I had indicated that there was a widespread concern in the country about the use of such money. I had broadly indicated, to which reference was made by the hon. Member, Shri Prakash Vir Shastri, that I also had the feeling that some foreign money did play a part in the elections of 1967.

The only point that was necessary for the Government to take into account was that instead of going into these past matters it is much better that we take certain steps so that we can prevent the recurrence of such things in future.

I will tell the House that we have decided to bring forward comprehensive legislation dealing with this problem.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : When?

SHRI Y.B. CHAVAN : I will explain that.

SHRI JYOTIRMOY BASU : What about the undesirable activities of the USIS in four places that I had told the Deputy Minister in External Affairs Ministry ? Is there something ready in your hand about that?

SHRI Y.B. CHAVAN : You have many points in your mind but I am sorry I cannot deal with them currently.

The major question that we have to take note of is that this foreign money in one form or the other, is having an adverse effect on our political, economic and cultural life. We have reached this broad conclusion. Now we have to find out the forms in which it is working and how we can effectively regulate it. This is the problem before us.

At the same time we have to see that in this process we do not regulate or restrict unduly the healthy relationship between one country and another, normal healthy commercial or other activities, relationship between one Government and another and other healthy exchanges between religious groups. These things also have to be taken note of. Therefore we have to go into this matter in a very careful and constructive manner because it is certainly a very complex question, more so because for the first time we are thinking in terms of having legislation of this type. Therefore we are drawing a sort of a list of principles which should be the basis of this legislation. We are in the process of preparing that list of principles and I propose to invite the Leaders of the Opposition to discuss first the principles.

Natuarlly, you would like me to indicate what type of principles they are. For example, the Bill that Shri Kanwar Lal Gupta has placed before us has stated one principle which is certainly the basic principle, namely, whoever receives any foreign aid must be made accountable. This is the principle which he has evolved. Of course, he says that such accounts should be laid on the Table of the House or should be given to Government. I do not think that it is necessary that Government should directly receive such things but we can certainly

[Shri Y. B. Chavan]

create authorities in different forms which can look into then. I do not think it will be necessary or wise for us to make it incumbent on anybody to lay all the accounts on the Table of the House. It will be rather very stupendous or unmanageable work. But I entirely agree with the basic principle which will have to be accepted that those who are receiving such amounts will have to be made accountable to Government. So, this principle will certainly be there.

Then we have to find out as to what it is that we want to restrict, whether it is going to be money that is received in the form of cash or in some other form. Assistance comes in the form of hospitality as well. So, we have to define all these matters. We have also to find out the source from which this assistance comes. It comes from Government, certain educational institutions, certain foundations and trusts and some religious bodies. So, we will have to think as to which source we have to take note of and mention in the Act.

I am merely indicating the lines on which we will have to sit down carefully and make up our own mind it. Having once accepted certain principles for legislation, we should not feel later on that we have acted rather hastily. So, it is much better to think properly about it, make up our minds and we should not take any party line in this matter because essentially it is a national problem. I do not think that any political party should take a party-line about it. Therefore, my effort will be to have some sort of a consensus evolved on this matter and certain principles decided on the basis of which then I propose to get the Bill drafted and bring it before the House. It will be a long process. But I think it is much better that we think beforehand than start thinking after drafting of legislation.

In view of this simple explanation, I would request the hon. Member, Shri Kanwar Lal Gupta, to withdraw the Bill.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : समापति जी, अभी जो मंत्री महोदय ने कहा है मैं मोटे तौर से उनकी भावनाओं से सहमत हूं और यह मैं मानता हूं कि जो विधेयक मैंने सदन के सामने रखा है शायद वह उतना कांप्रीहेंसिव न हो और उसके अन्दर और भी स्टडी करने की जरूरत है। इसलिए मंत्री से मैं यह कहूंगा कि यह इतना काम्प्लीकेटेड इश्यू बनाने से पहले मेरा ख्याल है कि एक साइंटिफिक स्टडी इसकी करा ली जाय कि किस तरीके से यह कहां कहां से आता है, मोडस आपरेंडी क्या है, इसके बार में एक साइंटिफिक स्टडी और एक डाटा इकट्ठा अगर हो जाय तब उसके बाद यदि इश्यू फ्रेम होंगे तो ठीक होगा। मेरा कहना यह है कि इन 20 सालों के अन्दर अभी तक सरकार ने कोई साइंटिफिक स्टडी इसका नहीं किया और उसके कारण कोई काम सरकार की तरफ से इसको रोकने के लिए नहीं किया गया। मुझे खुशी है कि सदन के चारों तरफ से इसका समर्थन हुआ है। केवल एक सोमानी साहब जो स्वतंत्र पार्टी के हैं, उन्होंने मेरे ऊपर मैकार्थीइज्म का चार्ज लगाया। मैं नहीं जानता कि यह उनकी निजी राय है, उनके निजी विचार हैं या स्वतंता पार्टी के विचार हैं। मैंने तो एक साधारण बात कही कि जो भी विदेश से धन आता है उसका एकाउन्ट होना चाहिए। अब इसमें इतना बड़ा आरोप लगाने की क्या जरूरत थी, यह मेरी समझ में नही आया। उन्होंने यह कहा कि रूस से रुपया आता है वह खराब है। तो रूस का रुपया तो खराब है और अमेरिका का अच्छा है? मेरी पार्टी इस को नहीं मानती। इसी तरह से कम्युनिस्टों ने कहा कि सी० आई० ए० का रुपया जो आता है वह खराब है लेकिन रूस के बारे में वह कुछ नहीं कहेंगे।

कम्युनिस्टों का तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन लोग यह कहते हैं कि कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी और हमारा एक एलायंस होने जा रहा है— मुझे मालूम नहीं कि अगर यह मेंटालिटी स्वतंत्र पार्टी की है तो मुझे दुख है समापति जी, इस मेंटालिटी के साथ हमारा काम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कोई भी रूस से, चीन से, अमेरिका से, जापान से कहीं से भी रुपया आए और कोई पार्टी हो, कोई संस्था हो या कोई नेता हो, अगर मेरी पार्टी का भी कोई नेता होगा तो हम उसको भी बख्शाने के लिए

तैयार नहीं हैं । जनसंघ का स्टैंड बहुत क्लीअर है । इसलिए मुझे दुख है और मैं समझता हूं कि यह स्टैंड केवल सोमानी जी का होगा, उनकी पार्टी का नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति कितनी भयानक है यह केवल 1967 तक ही नहीं जैसा कि गृह मंत्री महोदय ने कहा वहीं तक सीमित नहीं है, आज भी जो राज्य सरकारें टापल हो रही हैं उसमें विदेशी पैसे का हाथ है । इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता । यह पैसा बड़ी तेजी के साथ प्रभाव डाल रहा है । जब किसी भी राज्य सरकार पर कोई आफत आती है, सरकार बदलने वाली हाती है, आप देखिए यह एम्बेसीज कितनी तेजी से भागती हैं और मेरा कहना तो यह है कि केन्द्रीय सरकार के ऊपर भी यह विदेशी पैसा प्रभाव डाल रहा है । केन्द्रीय सरकार के चलाने पर, उनके विभिन्न मामलों पर भी उनका प्रभाव पड़े, इस बात की कोशिश उनकी ओर से है । इसमें हम लोग अगर सब सहमत हैं कि यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है, तो सब ने मिल कर कोई इसका जल्दी हल नहीं निकाला और देर इसमें की तो जो आप चाहते हैं वह उसका परिणाम नहीं होगा । एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा । गृह मंत्री शायद इस बात को स्वीकार करेंगे कि केवल कानून बनाने से काम चलने वाला नहीं है और जैसा उन्होंने सही कहा, यह एक राष्ट्रीय समस्या है, मैं उनसे कहूंगा कि आप या तो गृह मंत्री की हैसियत से सब पार्टियों के नेताओं को बुलाएं या प्रधान मंत्री बुलाएं और हर एक पार्टी के नेता को बुला कर पहले एक कोड आफ कान्डक्ट सब पोलिटिकल पार्टियों के लिए बनाया जाय कि विदेशी पैसे के प्रति उनका, उनके कार्यकर्ताओं का अथवा उनके नेताओं का क्या री-एक्शन होना चाहिए, क्या उनका कोड आफ-कन्डक्ट इस सिलसिले में होना चाहिए । इस प्रकार की एक मीटिंग बुला कर जो लोग विदेशों से सहायता लेते हैं जिनमें आज हमें बहुत सारे लोगों का मालूम है जो अमरिका से लेते हैं, चीन से लेते हैं, रूस से लेते हैं, वह पब्लिक की निगाहों में गिरें, उनको कंडेम करें, लोग उनको यह समझें कि यह देश के शत्रु हैं, इस प्रकार से जनता में जाकर के एक कार्यक्रम इस प्रकार का सबको मिला कर बनाना पड़ेगा और जब तक यह नहीं होगा, केवल कानून बनाने से काम चलने वाला नहीं है । इसलिए सभी को मिल कर के एक आवाज के साथ इसका समर्थन करना चाहिए । अभी आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि यू०के० के अन्दर एक पार्लियामेंट के मेम्बर पर मुकदमा चल रहा है इसलिए कि वह विदेशों से पैसा ले कर कुछ काम उनकी तरफ से कर रहे हैं । मुझे दुख है कि हमारे देश में ऐसा हो सकता है, मैं किसी का नाम देना नहीं चाहता लेकिन इस सदन में भी और कुछ दूसरे लेजिस्लेचर्स में भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो विदेशों से पैसा ले कर के वेस्टेड इन्टरेस्ट में यहां वकालत करते हों उनके लिए भी मैं आपके जरिए स्पीकर साहब से कहूंगा कि उनका भी कोई कोड आफ कान्डक्ट होना चाहिए और जिस तरह से इंग्लैंड में उसके ऊपर बहस छिड़ रही है कि एम०पीज० का क्या कोड आफ कान्डक्ट हो, इसी तरह विदेशों से पैसे लेकर कोई उनके गीत गाए, उनकी साइड में सदन को मोड़ने की कोशिश करे, इस बात को रोकने के लिए कोई तरीका सदन को भी सोचना चाहिए नहीं तो यह चीज बहुत आगे बढ़ेगी ।

जैसा गृह मंत्री महोदय ने कहा बहुत सारे देश हमारे बड़े बड़े एम०पीज० को बुलाते हैं और उनको मुफ्त में सैर कराते हैं तो इस संबंध में भी कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो एम० पी० जायें वह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की परमिशन लेकर सरकार के जरिए से जाने चाहिएं, यह मेरा मत है और इस प्रकार से कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा । नहीं तो ऐसा होगा कि कोई देश किसी को बुलाता है, वह वहां से लौट कर उसी के गीत गाता है, दूसरे को दूसरी कंट्री ने बुलाया वह वहां से आकर उसके गीत गाने लगता है, तो यह एक बहुत बड़े खतरे की बात है, यह चेतावनी मैं देना चाहता हूं......

(व्यवधान).......

[श्री कंवरलाल गुप्त]

18.18 hrs.

] MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

आखिर में मैं एक बात कहूंगा। बहुत सी चीजें गृहमंत्री महोदय के पास हैं। गृहमंत्री को पता भी है कि कहां से पैसा आता है। कई जगह छानबीन कर के यह निश्चित भी हो गया है कि यह पैसा बाहर से आता है। लेकिन मुझे दुख है कि सरकार ने अभी तक कोई ऐसी अच्छी मशीनरी नहीं बनाई जिस से इस काम के ऊपर निगाह रखी जा सके। छोटा सा एक सेल उसने बनाया लेकिन उस सेल से इतना बड़ा काम होने वाला नहीं है। मैं मांग करूंगा कि इसके लिए एक अच्छा सेल बनाया जाना चाहिए जो स्टेट्स के अन्दर भी और यहां भी। जहां-जहां भी यह कार्यवाही हो रही है उसको देख सके, क्योंकि यह जाल बिछाया जा रहा है बड़ी तेजी से और इसको रोकना बहुत जरूरी है। जो इसके कल्प्रिट्स हों उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसके अन्दर कोई पालिटिकल कंसिडरेशन नहीं आना चाहिए, चाहे वह किसी पार्टी का हो, कोई रिश्तेदार हो, या कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए क्यों कि देश की सेक्योरिटी, देश के डिफेंस के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हमारे अन्दर आपस में मतभेद हो सकता है, प्रजातंत्र में हम अलग अलग राय रख सकते हैं लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं है। देश की सेक्योरिटी पर अलग कोई बात आती है तो उसके लिए हम 100 और 5 मिल कर 105 हैं, और हम सब मिल कर उसका मुकाबिला करें।

इन शब्दों के साथ गृह मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उनकी भावनाओं की कदर करते हुए सदन से मैं यह चाहूंगा क वह मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना विधेयक वापस लूं और मैं आशा करता हूं कि इसमें गृह मंत्री देर नहीं लगाएंगे और इसे कोल्ड स्टोरेज में वह नहीं डालेंगे।

The Bill was by leave withdrawn.

18.20 hrs.

FREE LEGAL AID BILL*

श्री मधु लिमये (मुंघेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपराधिक अभियोगों में फंसे निर्धन और आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for free legal aid to poor and needy persons involved in criminal cases."

The Motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक को पेश करता हूं।

18.21 hrs.

DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) BILL*

Amendment of section 3,22, etc.

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Delhi Administration Act, 1966."

The Motion was adopted.

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं विधेयक को पेश करता हूं।

18.22 hrs.

CONSTITUTITON (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of Articles 85 and 174*)

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

---

* Published in Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 2, dated 13-3-70.